वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1990-91

कार्य प्रगति

Activities Report

1991-92

सत्यमेव जयते

भारतीय डाक विभाग

Department of Post, India

विषय सूची

प्रस्तावना	1
पुनरीक्षा	2
संगठन	6
डाक प्रचालन	8
डाक वित्त	16
मानव संसाधन	20
कार्य प्रगति (अप्रैल-दिसम्बर, 1991)	23

CONTENTS

Preamble	**25**
Overview	**26**
Organisation	**29**
Postal Operation	**31**
Postal Finances	**38**
Human Resources	**42**
Activities (April - December 1991)	**44**
Statistical Supplements	**46**

प्रस्तावना

डाक सेवा–संरचना और विशेषताएं

भारत में डाक सेवा एक प्रमुख सार्वजनिक सेवा है। यह सेवा लोगों के पत्रादि इकट्ठा कर उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। इस व्यवस्था को एक अधिनियम के तहत संचालित किया जाता है। इस अधिनियम से सरकार को इस सेवा के लिए वसूल किये जाने वाले शुल्क को तय करने और डाक सेवाएं किस प्रकार की हों, इसका निर्धारण करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा यह जो नियम निर्धारित करें उन्हें किस हद तक लागू किया जाए इस बात का भी अधिकार सरकार को दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन सरकार को पत्रों को लाने-ले जाने के एकाधिकार के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं जो पत्रों के अलावा अन्य किस्म की डाक के लिए भी लागू होते हैं।

डाक सेवा के जरिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुपये-पैसे भी भेजता है। इसके अलावा डाक सेवा सरकार के अन्य विभागों की ओर से समाज के प्रति अनेक अन्य दायित्व भी निभाती है।

पुनरीक्षा

पिछली रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी की जबरदस्त आवश्यकता पर जोर दिया गया था ताकि निजी कुरिअरों से प्रतियोगिता की जा सके और भारतीय डाक प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके। यद्यपि भारतीय डाक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अन्य देशों से पीछे रही है, फिर भी यह महसूस किया गया कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग अनिवार्य हैं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के लिए अनेक उपाय किए गए। डाक सेवा उत्कृष्टता पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ये उपाय किए गए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अपना मुख्य विषय बनाया था।

प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति

पिछले वर्षों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कमी रही। कुल मिलाकर जो प्रयास किए गए, वे अनियमित और अव्यवस्थित थे। तथापि वर्ष 1991-92 में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए। इलेक्ट्रानिक विभाग के विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराई गई। संक्षेप में, यह वर्ष प्रौद्योगिकी में प्रवेश का वर्ष कहा जा सकता है। डॉ. सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में संचार राज्य मंत्री द्वारा एक स्टीअरिंग ग्रुप का गठन किया गया। इसमें सचिव (डाक), सचिव (इलेक्ट्रानिक्स), महानिदेशक, एन.आई.सी. और डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया गया। प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रगति को मॉनीटर करने के लिए इसकी बैठकें होती रहीं। इन नियमित बैठकों से प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने और कठिनाईयों को दूर करने में सहायता मिली।

महत्वपूर्ण क्षेत्र

डाक विभाग में मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुविधानुसार मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :-

- कम्प्यूटरीकरण
- मनी ट्रांसफर सेवा के प्रयोग के लिए उपग्रह द्वारा नेटवर्किंग
- मशीनीकृत छंटाई
- डाक-टिकट, मुहर, डाक मशीन और उपस्कर

डाकघर कम्प्यूटरीकरण

इसमें लाभ और उपभोक्ता सन्तुष्टि बढ़ाने के लिए बहुद्देशीय काउंटर मशीनें शामिल हैं। इसमें लेखों और डाक-टिकटों, पोस्टल आर्डरों, बचत-पत्रों आदि जैसी लेखा-देय वस्तुएं और मूल्यवान उपकरण के केन्द्रीय समेकन शामिल हैं। 1990-91 के दौरान 102 बहुद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई। इस अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि और अधिक मशीनें लगाई जाएं जिससे और अधिक प्रगति हो सके। 1992-93 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालयों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण को भी प्रोत्साहित किया गया। इन परिणामों के आधार पर अन्य डाकघरों में चरणबद्ध तरीके से बचत बैंक कम्प्यूटरों की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। दो अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों के लिए ट्रेसिंग एवं ट्रैकिंग उपस्कर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 1992-93 के दौरान 12 अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में इस प्रकार की मशीन लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से कम्प्यूटरीकरण में प्रगति से डाकघरों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होने की संभावना है। इससे उपभोक्ता संतुष्टि में भी वृद्धि होगी।

उपग्रह मनीआर्डर सेवा

उपग्रह संचार के जरिए मनीआर्डर सूचनाएं प्रेषित करने के लिए 75 सूक्ष्म भू-स्टेशन इन्हें अति

सूक्ष्म एपरचर टर्मिनल्स - बी एस ए टी भी कहा जाता है। स्थापित करने की विभाग की योजना है। इससे मनीआर्डरों के प्रेषण के समय में काफी कमी होगी। इससे विशेष रूप से समाज के उन सदस्यों को लाभ होगा जो अपने परिवारजनों को शहरों से दूरस्थ या पहाड़ी क्षेत्रों में मनीआर्डर भेजते हैं। इससे निश्चित ही दक्षता बढ़ेगी और इसकी लागत मौजूदा दर से ही पूरी की जाएगी।

मशीनीकृत छंटाई

हाल ही में डाक विभाग और बेल टेलीफोन निर्माण कम्पनी, अंतवेर्प, बेल्जियम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अन्तर्गत बम्बई में स्वचालित एकीकृत डाक संसाधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस उपस्कर में दो पत्र छंटाई मशीनें और छः सूटों में 30 हस्तचालित कोडिंग डेस्क हैं। प्रत्येक कोडिंग डेस्क पर प्रचालक कोडिंग में पत्रों की तीव्र गति प्राप्त कर सकता है। कोड की गई डाक तीव्र गति से पत्र छंटाई मशीन द्वारा स्वतः छाँट ली जाएगी। इस उपस्कर से बम्बई में छँटाई के गत्यावरोध में कमी आएगी। यह मानवशक्ति योजना के लिए बेहतर सूचना आधार भी प्रदान करेगा।

डाक-टिकट, मुहर और डाक मशीन

विभाग ने डाक की मदों पर डाक की मुहर लगाने के लिए मशीन से खुदी स्टील की कड़ी मुहरों के निर्माण करने के लिए आदेश दिए हैं। इससे मुहर लगाने की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है। विभाग निर्माताओं के साथ बेहतर क्वालिटी की स्टैम्प विरूपण मशीनें और इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें खरीदने पर बातचीत कर रहा है।

नेटवर्क का विस्तार

8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के मानदण्डों की पुनरीक्षा के प्रश्न पर विचार किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को इसका अध्ययन करने के लिए कहा गया। उनकी सिफारिशों के आधार पर नए मानदण्डों पर अब अंतिम निर्णय ले लिया गया है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के मामले में ये मानदण्ड अपेक्षाकृत अधिक उदार हैं। सरकार ने इन मानदण्डों पर मंजूरी दे दी है और उन्हें ग्रामीण नेटवर्क विस्तार के उद्देश्यों से अपनाया जा रहा है। तथापि अब तक चलाए गए डाक विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ताकि यह देखा जा सके कि ग्रामीण विकास में यह कहां तक प्रभावी रहा है और उन डाकघरों को भी बंद किया जा सके जिनसे विभाग को घाटा हो रहा है और जो निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं।

वाशिंगटन सामान्य कार्य योजना

विश्व डाक संघ के सम्मेलन में वाशिंगटन सामान्य कार्य योजना पर अंतिम निर्णय लिया गया जिसे सभी डाक प्रशासनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज समझा जाता है। योजना का मूल दिग्विन्यास उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी करने से संबंधित था। इस उद्देश्य से मुख्यालयों में एक मार्किटिंग संगठन का गठन किया गया। इसके बाद विभिन्न सर्किलों में मार्किटिंग सेल की स्थापना की गई। मार्किटिंग सेल का कार्य और उपभोक्ता आवश्यकता पर उनके प्रभाव से डाक सेवाओं, विशेषकर स्पीड पोस्ट का विकास होगा। वर्ष 1991-92 के दौरान स्पीड पोस्टों में काफी प्रगति हुई। प्रचार और उन्नत मार्किटिंग तकनीकों को इसका श्रेय जाता है। तथापि इस समय स्पीड पोस्ट संगठन की एक निश्चित संरचना पर निर्णय करना आवश्यक है जिससे वाणिज्यिक पद्धति पर कार्यात्मक नम्यता सुनिश्चित की जा सके। सिर्फ इसी से स्पीड पोस्ट निजी कुरिअरों की कठोर प्रतियोगिता का सामना कर सकती है। विभाग भविष्य में स्वयं को इसी कार्य में लगाएगा।

फिलैटली

पिछली रिपोर्ट में यह बताया गया था कि विभाग डाक-टिकटों की छपाई के लिए बाहरी मुद्रकों की खोज में था। विभाग डीलक्स स्टेशनरी की शुरुआत भी करना चाहता था। इस दिशा में किए गए प्रयास सफल हुए और विभाग ने उच्च क्वालिटी के डाक-टिकट छापने के आर्डर दिए हैं। डाक-टिकट की रंग योजना सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि यह आकर्षक लगे। इन उपायों के द्वारा

यह कहा जा सकता है कि नासिक प्रतिभूति मुद्रणालय की पुरानी मशीनों की सीमाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं दूर हो गई हैं। विभाग अन्य देशों के लिए डाक-टिकटों की छपाई करने के विषय पर ध्यान दे रहा है और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने से देश के लिए विदेशी मुद्रा की रकम में काफी वृद्धि होगी।

घाटा

वर्ष 1990-91 में 1032.50 करोड़ रुपये का शुद्ध कार्यकारी व्यय हुआ जबकि राजस्व 840.85 करोड़ रुपए था। इस प्रकार पिछले वर्ष में 262.99 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में इस वर्ष 191.65 करोड़ रुपए घाटा हुआ। चूंकि सेवा के प्रत्येक मद की लागत सामान्यतः इस पर किए गए वास्तविक खर्च से काफी अधिक है, अतः भारतीय डाक व्यवस्था एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। इन घाटों को रोकने के लिए दरों में संशोधन करना एक उपाय हो सकता है। तथापि, यह दोहरे रूप से लाभप्रद है अर्थात, जब दर बढ़ती है तब मांग में लोच के परिणामस्वरूप परियात घट सकता है। डाक सेवा को एक सामाजिक सेवा के रूप में देखा जाता है और हमेशा लागत को ही ध्यान में रखकर दर निश्चित नहीं की जाती है। हल प्रत्यक्ष रूप से संरचनात्मक विकास और आधुनिकीकरण में ही निहित है जो दक्षता बढ़ाकर और लागत घटाकर घाटे को कम कर सकता है।

द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा

पिछली रिपोर्ट में यूनियनों और एसोसिएशनों की आशाओं पर प्रकाश डाला गया था जो यह महसूस कर रहे थे कि कर्मचारियों के लिए जो किया जा रहा था, वह पर्याप्त नहीं था। उन कर्मचारियों के लिए दूसरी समयबद्ध पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने सेवा के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने इसे द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा की योजना के एक भाग के रूप में स्वीकार कर लिया है जिसमें डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी एक महत्वपूर्ण भाग बनाया गया है। जबकि द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा आरम्भ कर दी गई है, यह देखना है कि किस तरह के संरचनात्मक सुधार लाने होंगे ताकि डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ दक्षता और उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सके। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उदाहरणार्थ सामूहिक बीमा योजना का आरम्भ करना।

पंचवर्षीय योजनाएं

1985-86 से 1989-90 तक की सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 195.80 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में वास्तविक खर्च 176.67 करोड़ रुपए अर्थात् कुल परिव्यय का लगभग 90 प्रतिशत हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं और इस योजना में मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाएगा। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु किए गए विभिन्न कार्यक्रम जारी रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई कमी न रह जाए, परियोजना प्रबन्धकों द्वारा विशेष परियोजनाएँ चलाई जायेंगी जो अन्त तक प्रगति को मॉनीटर करेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता काफी हद तक इन परियोजना प्रबन्धकों के कार्य पर भी निर्भर करेगी।

भविष्य के कार्यक्रम

यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेजी से बदलती हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए विभाग में नए सिरे से कार्य आरम्भ किया जाए, एक ठोस और दक्ष संगठन तथा इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। यह भी माना गया कि प्रबंधन को उत्तरदायी होना चाहिए और इसके लिए सर्किलों और क्षेत्रों के कार्य मॉनीटर किए जाने चाहिएं। शुरु की जाने वाली रॉलिंग ट्राफी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम सर्किल चुनने हेतु बेंचमार्क्स का सुझाव दिया गया। इस संदर्भ में दिसम्बर 1991 में पोस्टमास्टर जनरलों का अधिवेशन हुआ जिसमें अंतरसंबंधी मामलों के ग्रुपों पर विचार-विमर्श करने और उन पर सिफारिशें करने

के लिए उपसमितियां गठित की गईं। इन उप-समितियों ने डाक-प्रेषण और वितरण, काउंटर कार्य संपादन के प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सहित ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, सिविल विंग की संगठनात्मक संरचना, डाक सहायक, पोस्टमैन आदि के संवर्गों में पदोन्नति के लिए योग्यताओं में संशोधन, निरीक्षण पद्धति और रोधात्मक सतर्कता, डाक संगठन की पुनर्रचना, सर्वोत्तम सर्किल का मूल्यांकन करने के लिए कार्य-सूचकों और संसाधन के उत्पादन में कार्य स्तर का संचालन किया। सम्मेलन में इन उपसमितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया और इन विषयों पर लिए गए निर्णय विभाग के भविष्य के कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक आधार होंगे।

संक्षेप में, वर्ष 1990-91 को देश में डाक सेवाओं के विकास में एक संक्रांति काल के रूप में देखा जा सकता है। नई चुनौतियों का सामना करने और शुरु किए गए व्यापक अभिक्रमों को पूरा करने के लिए रचनात्मक अनुक्रियाओं की योजना तैयार की गई है। ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत प्रबंधन के साथ प्रौद्योगिकी के तालमेल के क्षेत्र में विभाग को सफलता प्राप्त होगी। विभाग की यह कोशिश होगी कि वह उत्पादकता को गिरने से रोके और दक्षता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार करे।

संगठन

तत्कालीन डाक-तार विभाग का विभाजन करने के पश्चात् जनवरी 1985 में डाक विभाग का सृजन किया गया था। यह संचार मंत्रालय का एक अंग है। विचाराधीन अवधि के दौरान संचार मंत्रालय डॉ. संजय सिंह, संचार राज्य मंत्री के नियंत्रण में था। फिलहाल संचार मंत्रालय श्री राजेश पायलट, संचार राज्य मंत्री के नियंत्रण में है। श्री पी.वी. रंगय्या नायडू फिलहाल संचार उप मंत्री हैं।

मुख्यालय

विभाग की प्रबंध व्यवस्था डाक सेवा बोर्ड करता है जिसके चार सदस्य और एक अध्यक्ष हैं। सचिव डाक विभाग, डाक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सदस्यों को प्रचालन, विकास, कार्मिक और वित्त के कार्य सौंपे गए हैं। बोर्ड में एक सचिव हैं।

सचिव, डाक विभाग महानिदेशक, डाक भी हैं। बोर्ड की सहायता के लिए उप महानिदेशक हैं।

सर्किल

विभाग के प्रचालन दायित्वों को निभाने के लिए पूरे देश को 19 सर्किलों में बांटा गया है। एक सर्किल में एक अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। सर्किल के अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल होते हैं। जिन 16 सर्किलों के अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल हैं उन्हें क्षेत्रों में बांटा गया है इन क्षेत्रों में डाक डिवीजनों के अनेक ग्रुप हैं अथवा उनकी सहायता के लिए उनमें एक पोस्टमास्टर जनरल है। इनमें से 7 सर्किलों - आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के पद 7300-7600 रु. के ग्रेड में हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित क्षेत्रीय डाक योजना इकाईयां भी इस कार्य में बेहतर व्यावसायिकता लाने के लिए पोस्टमास्टर जनरल के स्तर के प्रशासकों के अधीन हैं। सर्किल में मेल डिवीजन, स्टोर डिपो, स्टैंप डिपो और मेल मोटर जैसे कार्यात्मक डिवीजन और यूनिटें भी हैं।

डाकघरों की मुख्य डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघरों जैसी श्रेणियां हैं। शाखा डाकघर अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं तथा उप डाकघर अधिकतर विभागीय डाकघर हैं। मुख्य डाकघरों को उनके आकार के अनुसार पांच श्रेणियों में बांटा गया है इनमें से सबसे बड़े डाकघर प्रेजीडेंसी डाकघर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हैं।

सेना डाक सेवा के अध्यक्ष मेजर जनरल होते हैं जिन्हें अपर महानिदेशक का पदनाम दिया गया है। सेना डाक सेवा को एक डाक सर्किल के रूप में मान्यता दी गई है।

स्थिति

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, डाक सेवा बोर्ड में श्री कैलाश प्रकाश, सचिव (डाक) और महानिदेशक डाक, श्री एस. कृष्णन, सदस्य (वित्त) श्री एस. पी. गुलाटी सदस्य (प्रचालन), श्री एम. एस. पॉलराजन, सदस्य (विकास) और श्री पी. आर. राव, सदस्य (कार्मिक) थे। श्री वी. एस. ऐलावादी, सचिव, डाक सेवा बोर्ड थे।

इस समय 17 दिसम्बर, 1991 से श्री एस. पी. गुलाटी, डाक विभाग के सचिव हैं। फिलहाल श्री एल. डी. बोनल सदस्य (कार्मिक) हैं और श्री सी. पी. थॉमस, सदस्य (विकास) का कार्य देख रहे हैं। श्री एस. के. एन. नैय्यर, सदस्य (वित्त), दूरसंचार सदस्य (वित्त), डाक विभाग का अतिरिक्त पदभार संभाले हुए हैं। फिलहाल श्री वाई. एल. राजवाड़े, डाक सेवा बोर्ड के सचिव हैं।

1981-82 से डाक परियात

(दस लाख में)

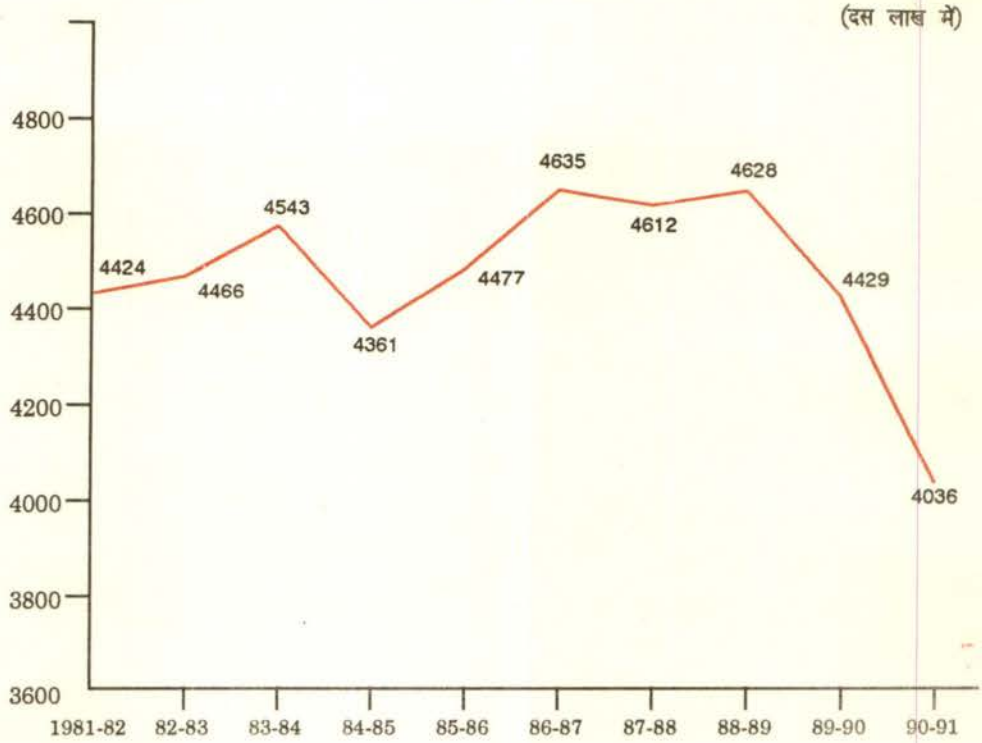

मदवार डाक परियात

(दस लाख में)

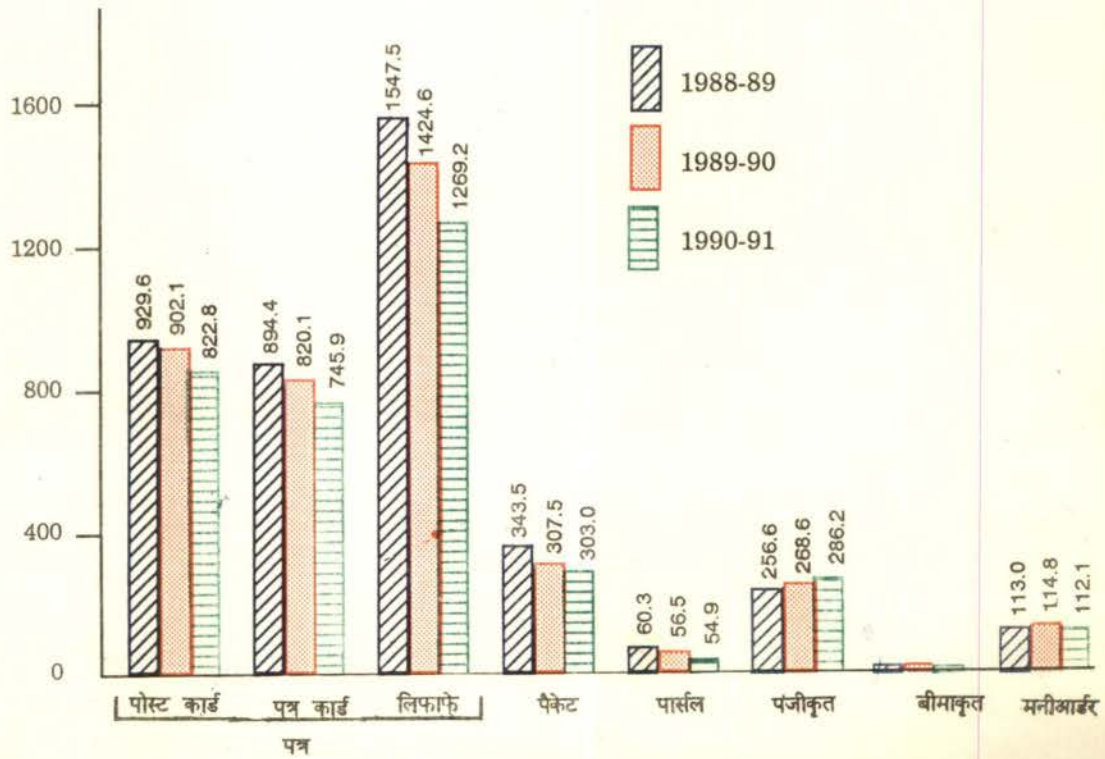

डाक मात्रा

वर्ष के दौरान 3287 मिलियन अंतर्देशीय गैर-पंजीकृत डाक मदों का निपटान किया गया जिसमें 2778 मिलियन पत्र, 476 मिलियन पैकेट और 33 मिलियन पार्सल सम्मिलित हैं। अंतर्देशीय पंजीकृत डाक की संख्या 311 मिलियन है। पिछले वर्ष की तुलना में 1990-91 में पंजीकृत डाक में वृद्धि हुई है जबकि गैर-पंजीकृत डाक में कमी आई है।

डाक विभाग ने वर्ष के दौरान 105.8 मिलियन मनीऑर्डरों के भुगतान किए जिनका कुल योग 29372 मिलियन रुपए था। पोस्टल आर्डर के जरिए कुल 236.2 मिलियन रुपयों का भुगतान किया गया।

स्पीड पोस्ट

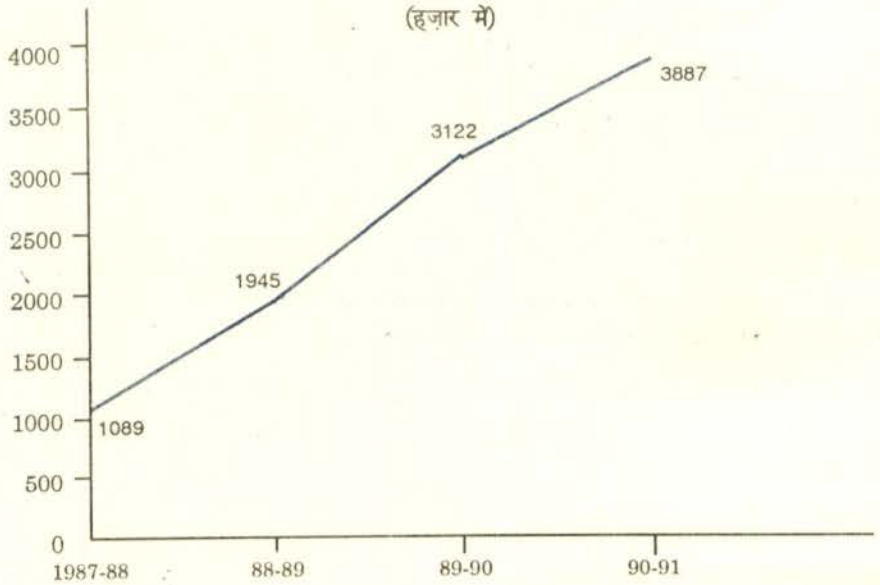

स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट के लिए 60 केन्द्र है। दिनांक 1.4.90 से 31.3.91 की अवधि के दौरान निम्नलिखित केन्द्र खोले गये :

त्रिचूर 4.6.1990 से
जालंधर 16.8.1990 से
लुधियाना 12.10.1990 से

दिनांक 12.10.1990 से प्वाइंट टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा और विशेष ग्राहक सेवा, ठेका स्पीड पोस्ट सेवा और स्पीड पोस्ट पिक अप सेवा प्रारम्भ की गई। दिनांक 1.12.1990 से स्पीड पोस्ट की दरें युक्तिसंगत बना दी गई हैं। स्पीड पोस्ट मदों के वितरण तथा बुकिंग के लिए दिनांक 1.11.90 से प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर दिया गया है।

दिनांक 1.4.90 से 31.3.91 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित किये गये हैं :

इंडोनेशिया	1.5.1990 से
सउदी अरब	1.5.1990 से
चीन गणराज्य	1.9.1990 से
श्रीलंका	1.9.1990 से
मालदीव	11.9.1990 से

इसी अवधि के दौरान त्रिचूर, जालंधर और लुधियाना में तीन अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुकिंग केन्द्र खोले गये।

प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन

जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा ने मूल रूप से दो मुद्दों पर बल दिया है :-

(1) डाक मशीनीकरण; और (2) काउंटर मशीनीकरण। डाक का वितरण शीघ्रता से करना शीघ्र डाक छंटाई पर निर्भर करता है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर आदि मुख्य महानगरों में प्रतिदिन छंटाई की जाने वाली डाक की मात्रा 2 मिलियन से भी अधिक है डाक की मात्रा के अतिरिक्त विभाग को इस समय व्यस्ततम घंटों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हुए डाक परियात की अपेक्षा मानव छंटाई

विश्व डाक संघ से संबंध

विश्व डाक संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है, डाक प्रशासन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस वर्ष के दौरान 170 देश इस संघ के सदस्य रहे। भारत विश्व डाक संघ के डाक अध्ययन की सलाहकार परिषद् के सदस्य और एशियाई प्रशान्त डाक संघ (एपीपीयू) के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डाक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इन दोनों संघों में भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यथा सी सी पी एस की समिति 7 का अध्यक्ष और ए पी पी यू के तकनीकी सहयोग और सहायता से संबंधित स्थाई समिति का अध्यक्ष।

ए पी पी यू का छठा सम्मेलन 25 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1990 तक न्यूजीलैंड के रोटोरुआ में आयोजित किया गया था। कांग्रेस ए पी पी यू का सर्वोच्च निकाय है तथा इसकी बैठक प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार की जाती है। इसकी बैठक यू पी यू सम्मेलन होने के सामान्यतः दो वर्षों के भीतर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, डाक सेवाओं से संबंधित तकनीकी, प्रचालन और आर्थिक विषयों पर अध्ययन कार्यक्रम की तैयारी तथा आगामी पांच वर्षों के लिए क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की नीतियों के सिद्धांत इस सम्मेलन में निर्धारित किए जाते हैं। श्री कैलाश प्रकाश सचिव, डाक विभाग की अध्यक्षता में छः सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने छठे ए पी पी यू सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य सर्वश्री एम.एस. पॉलराजन, सदस्य (विकास), एस. कृष्णन, सदस्य (वित्त), बी.टी. मेंघानी, सदस्य (कार्मिक), एन. के. वर्मा, उपमहानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और राघव लाल, निदेशक (बचत बैंक/अंतर्राष्ट्रीय संबंध) थे। भारत को ए पी पी यू की एक महत्वपूर्ण समिति, तकनीकी सहयोग और सहायता की स्थाई समिति का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। ए पी पी यू क्षेत्र में वाशिंगटन सामान्य कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की अध्यक्षता करने हेतु भारत को आमंत्रित किया गया।

श्री कैलाश प्रकाश, सचिव, डाक विभाग के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर, 1990 में सी सी पी एस के वार्षिक सत्र में भी भाग लिया। सी सी पी एस की समिति 7 के अध्यक्ष के रूप में भारत सी सी पी एस की संचालन समिति का भी सदस्य है। यह समिति सी सी पी एस द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययनों की प्रगति पर विचार-विमर्श करती है और इसके भविष्य के विषयों पर मार्गनिर्देश करती है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठक

भारत ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भी भाग लिया। एक सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 1990 में मास्को, सोवियत संघ में आयोजित फिलैटली प्रदर्शनी में भाग लिया। एक सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 1990 में सिंगापुर में आयोजित विश्व डाक-टिकट प्रदर्शनी सिंगापेक्स में भाग लिया। श्री एन.के. वर्मा, उपमहानिदेशक (बचत बैंक संगठन) ने कम्प्यूटरीकृत बचत बैंक लेखा और जी आई आर ओ प्रणाली की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए फ्रांस का दौरा किया। उन्होंने रोम के अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान में आयोजित सोलहवें विश्व सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने जून 1990 में माले में आयोजित डाक सेवाओं पर सार्क तकनीकी समिति की नौवीं बैठक में भी भाग लिया।

डाक प्रचालन

प्रस्तावना

डाक प्रचालन का प्रायः एक ही कार्य समझा जाता रहा है, पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण करना। वास्तव में यह कार्यों के अंतः संबंधों की बहुरंगी कड़ी है और इस प्रचालन की सफलता अक्सर परिवहन क्षेत्र की दूसरी एजेंसियों जैसे एयर लाइन और रेलवे की दक्षता पर निर्भर करती है। डाकघर दूसरे मंत्रालयों/विभागों के कार्य जैसे बचत बैंक और डाक जीवन बीमा आदि के कार्य भी करता है जो एजेंसी कार्य के नाम से जाने जाते हैं।

डाक नेटवर्क का विस्तार

31 मार्च, 1991 को डाक नेटवर्क में 148719 डाकघर थे जिनमें से 132646 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 16073 डाकघर शहरी क्षेत्रों में थे। वर्ष 1990-91 में अकेले ही 1476 ग्रामीण डाकघर मंजूर किये गये थे। प्रत्येक डाकघर औसतन 22.10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और 4607 व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करता है। विकास के इस स्तर के साथ देश में विश्व डाक संघ द्वारा अपनाये गये मानदंडों के अनुसार देश में या तो औसतन 20 से 40 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में एक डाकघर होना चाहिए या फिर 3000 से 6000 की आबादी को डाक सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए एक डाकघर होना चाहिए। देश में कुल 520074 लैटर बॉक्स थे जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 436667 तथा शहरी क्षेत्रों में 83407 लैटर बॉक्स थे।

डाकघरों की संख्या

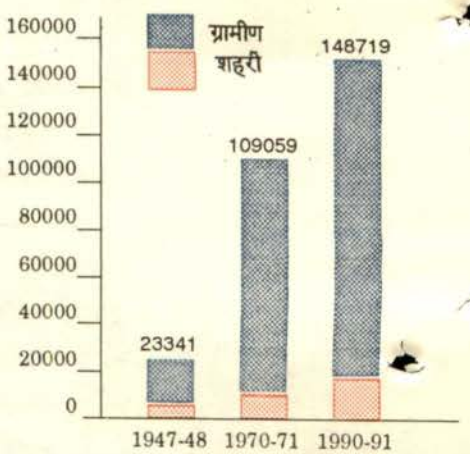

548 डाक कार्यालयों के नेटवर्क द्वारा डाक का निपटान किया जाता है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कोचीन और पटना में 6 अंतर्राष्ट्रीय डाक विनिमय कार्यालय हैं। डाक परिवहन वायुयान, सड़क तथा रेलगाड़ियों द्वारा किया जाता है।

सेवाएं

प्रदत्त की जाने वाली डाक सेवाएं

डाक सेवाएं,

अर्थात् पत्र, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- लिफाफे
- लेटरकार्ड
- पोस्टकार्ड
- **बुक पैकेट**
- **न्यूजपेपर पैकेट**
- **पार्सल**

इनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:

- साधारण डाक
- पोस्टिंग सर्टिफाइड आर्डीनरी मेल
- रिकार्डिड डिलीवरी
- रजिस्ट्रेशन
- वैल्यूपेबल
- बीमा
- स्पीड पोस्ट

धन अंतरण सेवाएं

अर्थात्

- मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर

अन्य सेवाएं

अर्थात्, बचत बैंक

- डाक जीवन बीमा, तार
- टेलीफोन पब्लिक काल आफिसेज
- टेलीफोन रेवेन्यू कलेक्शन

प्रणाली काफी कमजोर है। इसका एक ही उत्तर है डाक छंटाई का मशीनीकरण। इस उद्देश्य के लिए बम्बई में प्रारम्भ की गई परियोजना को पायलट परियोजना का नाम दिया गया है, जिसे बाद में दूसरे महानगरों में लागू किया जायेगा। काउंटर मशीनीकरण विश्वास का दूसरा क्षेत्र है। जनता को एक ही काउंटर पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर और लखनऊ में प्रायोगिक तौर पर 102 पर्सनल कम्प्यूटर आधारित बहु उद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं। इन उपस्करों की कार्य-क्षमता को विभिन्न स्थानों पर बड़ी बारीकी से मॉनीटर किया जा रहा है।

स्टैम्प के चिन्ह के सुधार के लिए हार्ड स्टील की मशीन से बनी स्टैम्प उपलब्ध कराने से संबंधित मामले पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रबंध सूचना प्रणाली, प्रधान डाकघर लेखा प्रणाली की भांति कार्यालय से इतर कार्य को भी विशेष रूप से कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली के साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

मेल - मोटर सेवाएं

वर्ष 1990-91 के दौरान देश के 90 स्थानों पर विभागीय मेल मोटर सेवा अस्तित्व में थीं वर्ष के दौरान समीक्षा के अंतर्गत डाक के त्वरित पारेषण तथा कार्य-क्षमता को बनाये रखने और इसमें सुधार के लिए पुरानी गाड़ियों के स्थान पर 158 नई गाड़ियां खरीदी गई थीं। वर्ष 1990-91 के अंत में मेल-मोटर गाड़ियों की कुल फ्लीट सं. 1103 थी।

फिलैटली

वर्ष 1990-91 के दौरान 41 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किये गये थे। इसी अवधि के दौरान महात्मा गांधी पर 100 पैसे के मूल्य का एक डाक-टिकट जारी किया गया। 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार 49 फिलैटलिक ब्यूरो 173 फिलैटलिक काउंटर मौजूद थे।

इस अवधि के दौरान सर्किल स्तर की निम्नलिखित फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं :-

गूजा पेक्स - 90	दिनांक 25.5.90 से 27.5.90 तक गुजरात सर्किल के लिए अहमदाबाद में।
राज पेक्स - 90	दिनांक 23.8.90 से 26.8.90 तक राजस्थान सर्किल के लिए जयपुर में।
चंडी पेक्स - 90	दिनांक 31.8.90 से 2.9.90 तक हरियाणा और पंजाब सर्किल के लिए चंडीगढ़ में।
मापेक्स - 90	दिनांक 20.9.90 से 23.9.90 तक मध्य प्रदेश सर्किल के लिए भोपाल में।
महापेक्स - 90	दिनांक 21.9.90 से 24.9.90 तक महाराष्ट्र सर्किल के लिए बम्बई में।
टानापेक्स - 90	दिनांक 4.10.90 से 7.10.90 तक तमिलनाडु सर्किल के लिए कोयम्बतूर में।
करनापेक्स - 90	दिनांक 12.10.90 से 14.10.90 तक कर्नाटक सर्किल के लिए बंगलौर में।
यूफलीपेक्स - 90	दिनांक 26.11.90 से 29.11.90 तक उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए लखनऊ में।
डाकियाना -	दिनांक 31.1.91 से 3.2.91 तक दिल्ली सर्किल के लिए दिल्ली में।

विभाग ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया:

सिंगापेक्स - 90	दिनांक 16.8.90 से 19.8.90 तक सिंगापुर में।
न्यूजीलैंड - 90	दिनांक 24.8.90 से 2.9.90 तक आकलैंड में।
वियन - 90	दिनांक 29.8.90 से 2.9.90 तक वियना में।
स्पोर्टीफिलेक्स-90	दिनांक 22.9.90 से 3.10.90 तक बीजिंग में।

दिनांक 16.8.90 से 18.8.90 तक मास्को और नई दिल्ली में पारस्परिक आधार पर फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।

एजेन्सी सेवाएं

डाकघर बचत बैंक

डाकघर बचत बैंक सबसे बड़ा बैंक है जिसमें 93.40 मिलियन खातें हैं जिसमें 177560 मिलियन रुपये जमा हैं। डाकघर बचत बैंक वित्त मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित स्कीम चलाता है:

- बचत खाता
- आवर्ती जमा खाता
- सावधि जमा खाता
- राष्ट्रीय बचत योजना
- मासिक आय योजना
- लोक भविष्य निधि
- इन्दिरा विकास पत्र
- किसान विकास पत्र
- राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम

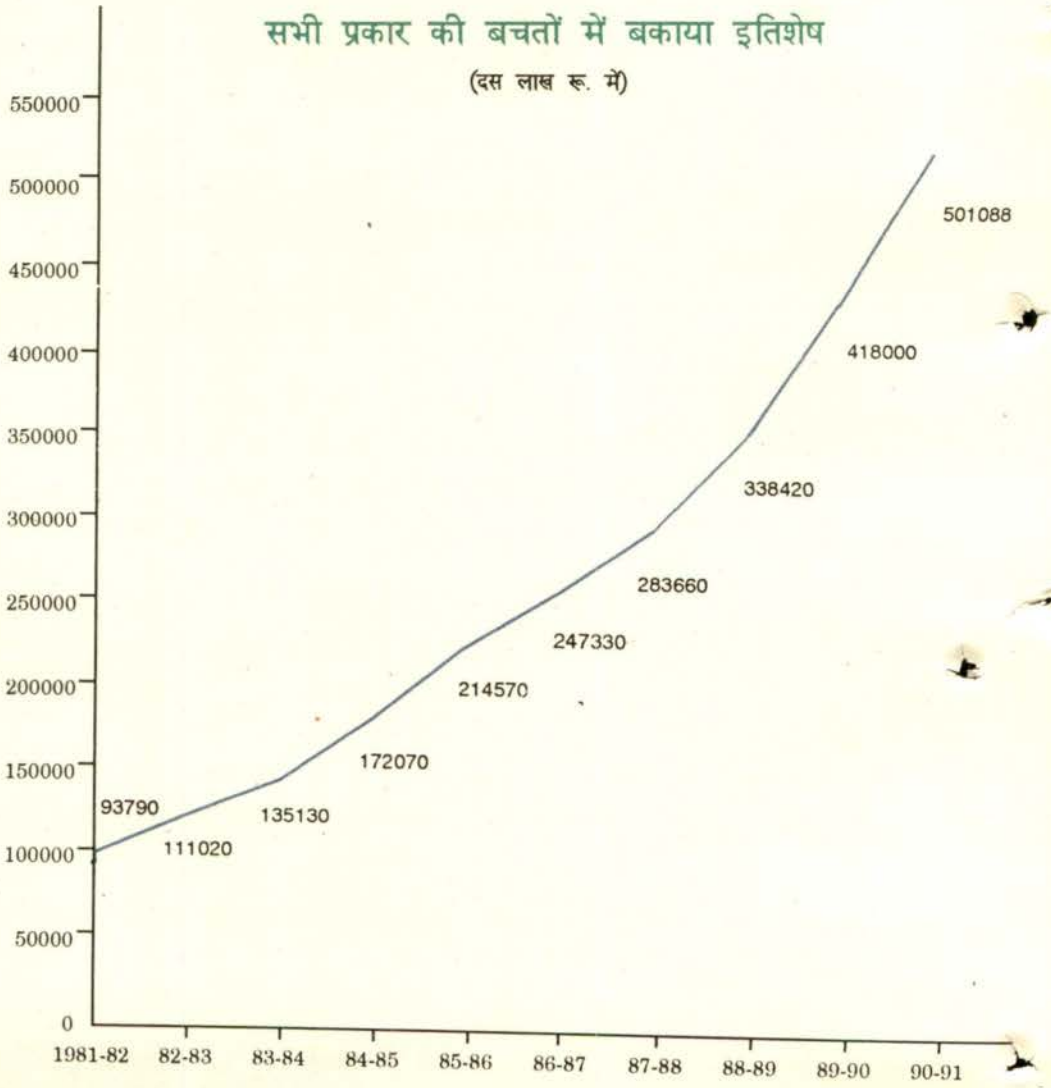

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा निम्नलिखित 4 पालिसी प्रदान करती है:

- बंदोबस्ती बीमा
- आजीवन बीमा
- परिवर्तित आजीवन जीवन बीमा
- प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा 15 और 20 वर्ष

पिछले 4 वर्षों के दौरान घोषित बोनस निम्न प्रकार है :

पिछले वर्ष 15,79,481 पालिसियों पर 2119.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया, जबकि वर्ष 1990-91 में यह बढ़कर 16,91,754 पालिसियों पर 2567.85 करोड़ रुपये हो गया। 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात सर्किल में सबसे अधिक 2,44,131 पालिसियां थीं। वर्ष

1990-91 में 1,56,358 पालिसियों द्वारा 476.27 करोड़ रुपये का कारोबार किया जो पिछले वर्ष के 1,62,510 पालिसी के 432.49 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। गुजरात और कर्नाटक सर्किल ने क्रमशः 26219 और 20515 पालिसियों पर 89.34 करोड़ रुपये और 53.06 करोड़ रुपये के कारोबार की वृद्धि की।

	आजीवन बीमा (प्रति बीमा 1000 वार्षिक)	बंदोबस्ती बीमा
1987-88	78 रुपये	63 रुपये
1988-89	80 रुपये	65 रुपये
1989-90	83 रुपये	67 रुपये
1990-91	85 रुपये	70 रुपये

कुल पालिसियों की संख्या

(दस लाख रू. में)

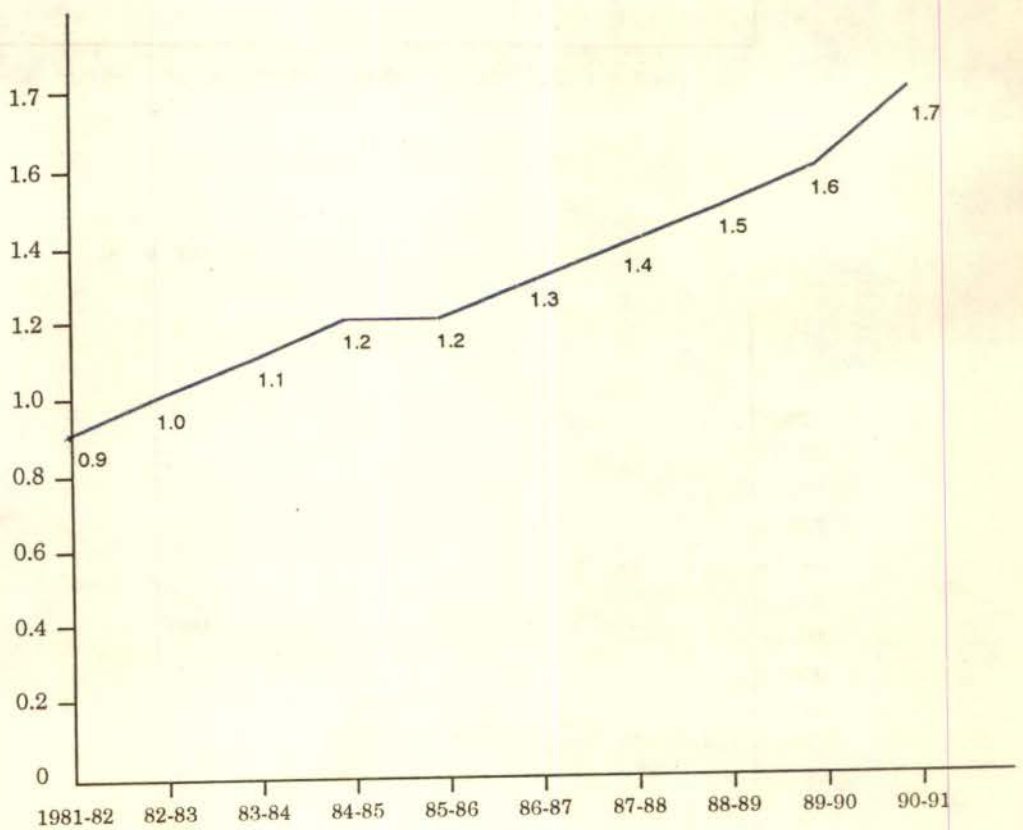

कुल बीमाकृत राशी

(दस लाख रू. में)

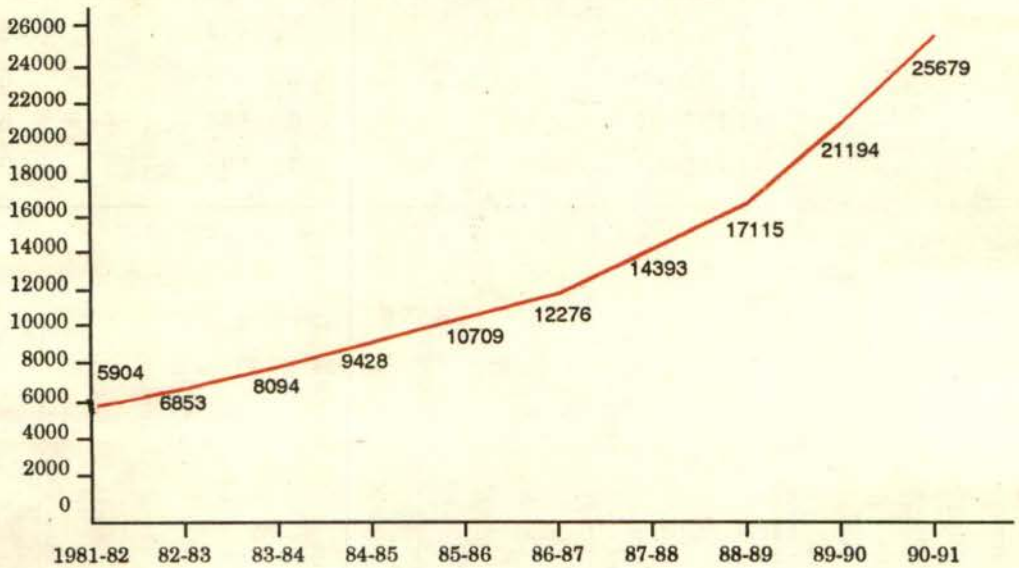

जीवन बीमा निधि

(दस लाख रू. में)

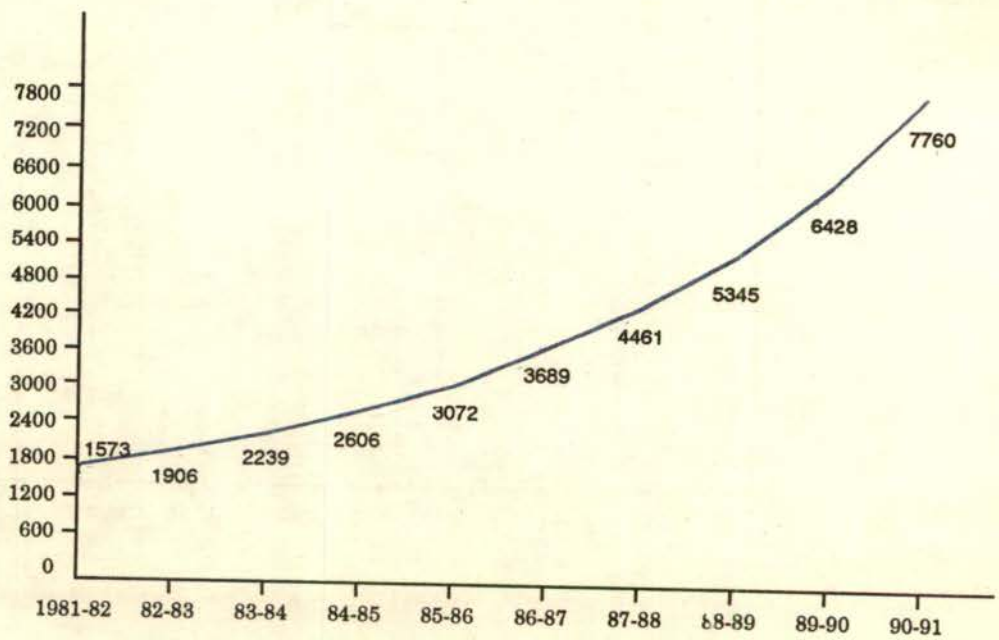

महत्वपूर्ण वर्गों का सकल व्यय निम्न प्रकार है:-

वेतन एवं भत्ता, आकस्मिक व्यय और अन्य मदें	952.05	1004.60	5.5
पेंशन संबंधी प्रभार	110.18	150.31	36.4
लेखा एवं लेखा-परीक्षा	28.99	30.88	6.5
डाक-टिकट तथा लेखन सामग्री	42.23	34.77	(-) 17.7
लेखन सामग्री एवं मुद्रण आदि	18.93	23.41	23.7
परिसंपत्ति इत्यादि का रखरखाव	7.12	1.49	(-) 79.1
छुट-पुट कार्य	1.04	1.48	42.3
डाक की ढुलाई (रेलवे तथा एयर मेल कैरियर का भुगतान)	58.07	55.92	(-) 3.7
जोड़	1218.61	1302.86	6.9

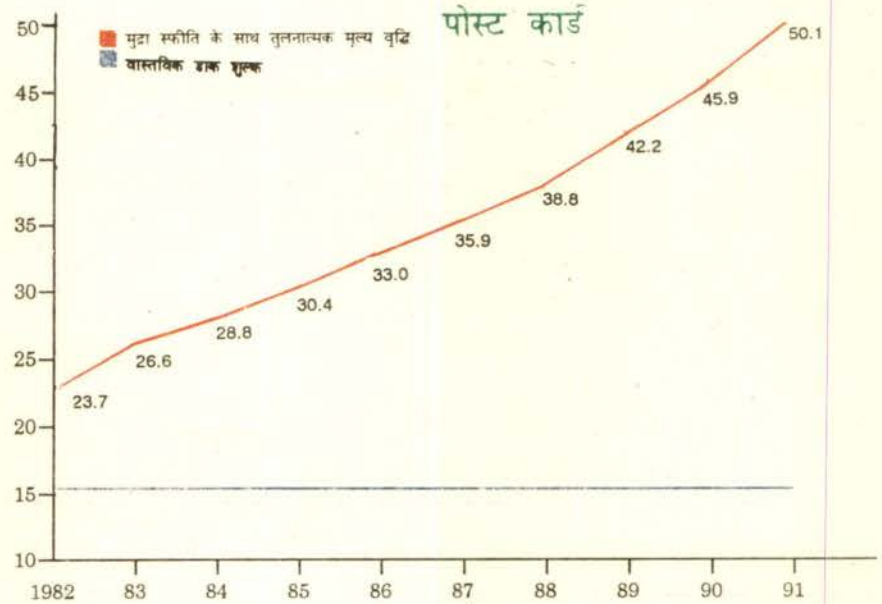

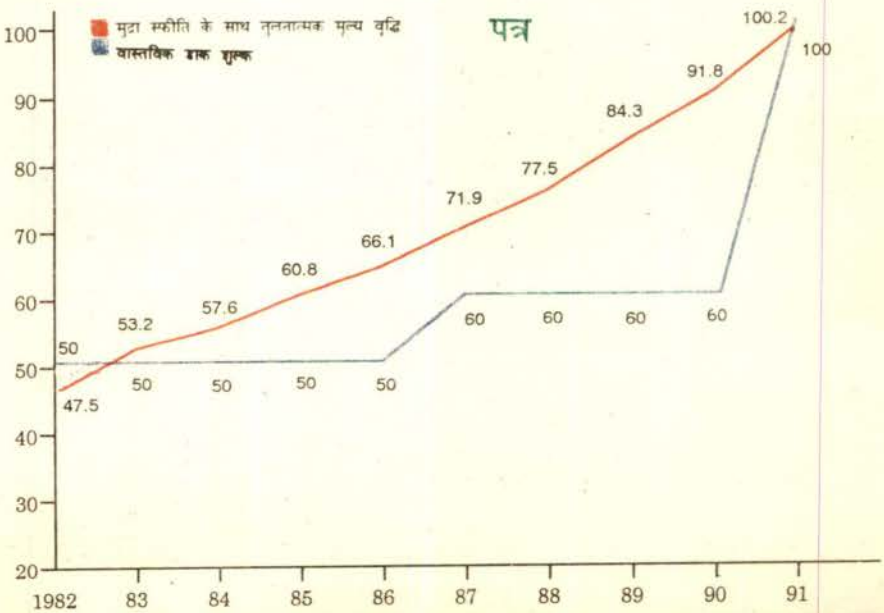

पत्र कार्ड

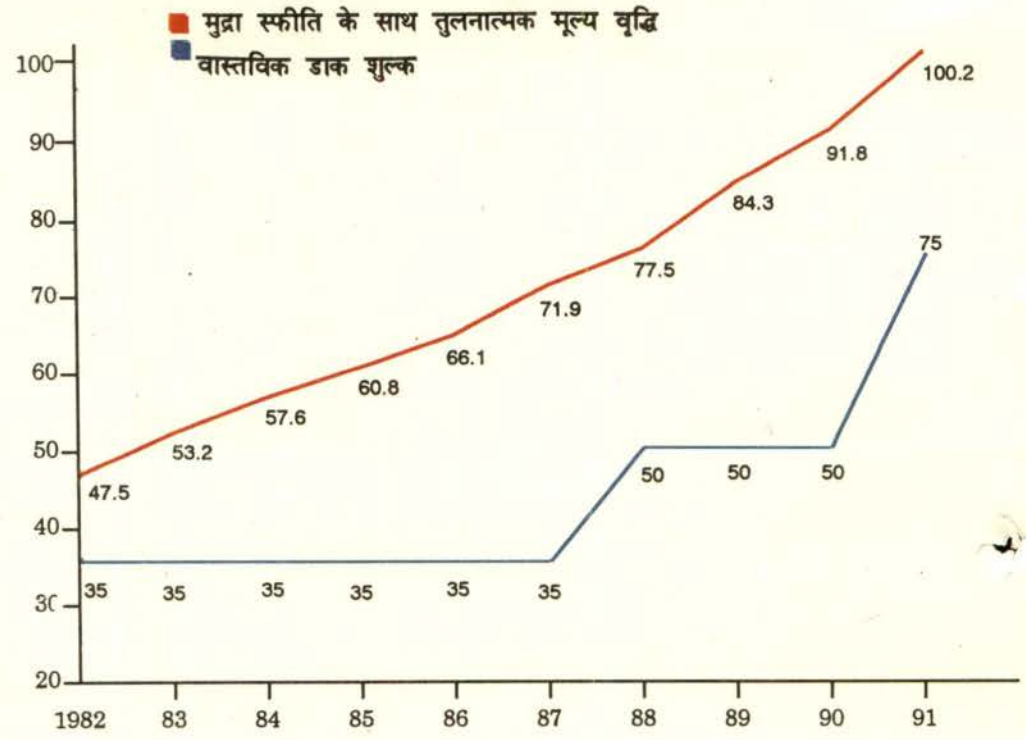

राजस्व और व्यय

(दस लाख रू. में)

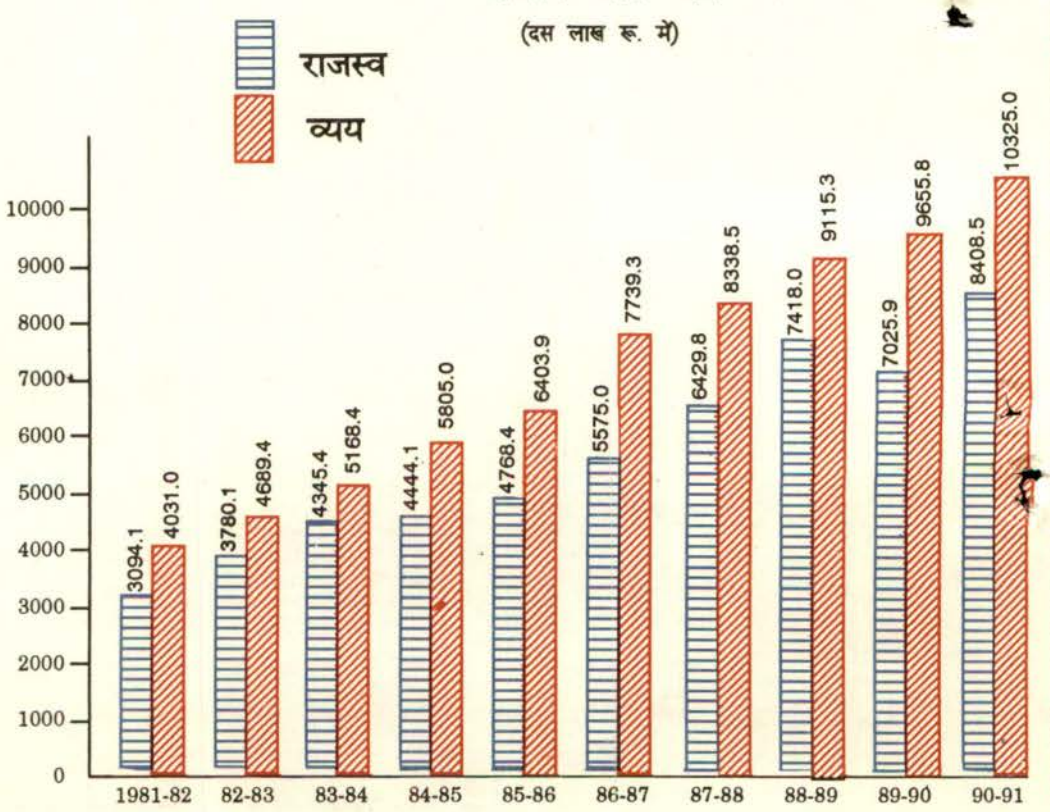

ग्राहक संतुष्टि

समीक्षाधीन अवधि अर्थात वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 682599 शिकायतें प्राप्त हुई और 1989-90 के वर्ष में 710597 शिकायतों की जांच की गई। 1990-91 में शिकायत की दर कुल परियात का 0.00461% थी जो पिछले वर्ष की दर 0.00486% से थोड़ा कम है।

पुनः प्रेषण पत्र

वर्ष 1990-91 के दौरान विभाग के 15 पुनः प्रेषण कार्यालयों द्वारा जो गैर-वितरित डाक का हिसाब रखते हैं 32.8 मिलियन पत्रों का निपटान किया गया उनमें से 53% पत्रों के पतों में सुधार करके उन्हें पाने वाले तक पहुंचाया गया और 27% पत्रों को उनका पता सुनिश्चित करने के बाद भेजने वाले के पास भेज दिया गया।

डाक परिसर

विभाग ने वर्ष के दौरान अपनी भवन निर्माण संबंधी गतिविधियां 28.03 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ा दी और 91 कार्यालय भवन तथा 105 स्टाफ कवार्टरों का निर्माण कार्य जो पिछले वर्षों से चल रहा था को पूरा करने के अतिरिक्त नई परियोजना के रूप में 105 भवन और 157 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रगति पर था। वर्ष के अंत में 192 कार्यालय भवन और 395 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। वर्ष 1990-91 के लिए 361 कार्यालय भवन जिसमें मौजूदा भवन के विस्तार से संबधित 52 कार्य सहित और 808 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य को नई परियोजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। विभाग ने वर्ष के दौरान 2.08 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर व्यय किया और 77 स्थान अधिग्रहीत किये गये थे।

डाक वित्त

1986-87 से पिछले पांच वर्षों में डाक सेवाओं पर 1031.67 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ।

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपयों में)
1986-87	216.43
1987-88	190.87
1988-89	169.73
1989-90	262.99
1990-91	191.65

वर्ष 1990-91 का कुल राजस्व 840.85 करोड़ रुपये था जो कि पिछले वर्ष के 702.59 करोड़ रुपये की तुलना में 138.26 करोड़ रुपये (लगभग 19.7%) अधिक था। यह वृद्धि मुख्य रूप से 11 जून, 1990 से कुछ डाक सामग्री की दरों में संशोधन किये जाने के कारण हुई। वर्ष में राजस्व की वसूली अनुमानित राजस्व का 93.4% की गयी जो 59.15 करोड़ रुपये कम था।

पिछले वर्ष 965.58 करोड़ रुपये व्यय की तुलना में वर्ष की कुल कार्यकारी व्यय 1032.50 करोड़ रुपये था (अर्थात लगभग 6.9% रुपये की वृद्धि) और अनुमानित व्यय 1059.38 करोड़ रुपये था जैसा कि संशोधित प्राक्कलन 1990-91 में दर्शाया गया है। व्यय में वृद्धि मुख्यतया उच्च कर्मचारी लागत और अधिक पेंशन प्रभारों के कारण हुई थी। निम्नलिखित लेखा पद्धति में परिवर्तन सामान्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ।

राजस्व तथा व्यय 1990-91

(वर्ष 1989-90 की तुलना में)

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरे	1989-90	1990-91	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
	राजस्व		
डाक-टिकटों की बिक्री	431.64	511.66	18.5
नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	133.65	173.18	29.6
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर से प्राप्त कमीशन	105.55	110.46	4.7
अन्य प्राप्तियां	31.75	45.55	43.5
जोड़	702.59	840.85	19.7
	व्यय		
सामान्य प्रशासन	80.25	83.28	3.8
प्रचालन	618.94	643.93	4.0
एजेंसी सेवाऐं	33.62	34.30	2.0
अन्य	232.77	270.99	16.4
जोड़	965.58	1032.50	6.9

सेवाओं की लागत

वर्ष 1990-91 और पिछले वर्ष में मुख्य सेवाओं की लागत एवं राजस्व नीचे प्रत्येक सेवा के सामने दर्शाए गए हैं :-

(आंकड़े रुपयों में)

सेवा	1989-90		1990-91	
	लागत	राजस्व	लागत	राजस्व
पोस्टकार्ड	1.11	0.15	1.17	0.15
मुद्रित पोस्टकार्ड	1.07	0.40	1.09	0.60
लेटर कार्ड	1.25	0.43	1.28	0.75
पत्र	1.28	1.29	1.29	1.81
पार्सल	17.10	10.25	14.61	14.31
मनीआर्डर	10.62	8.76	11.51	8.99
रजिस्टर्ड	7.78	5.00	8.20	6.00
बीमाकृत	10.23	9.20	10.77	18.12
पैकेट				
बुक पैकेट	1.63	1.20	1.58	2.42
मुद्रित बुक पैकेट	2.08	0.83	1.96	2.26
अन्य	2.29	0.99	2.15	2.11

एजेंसी सेवाएं

वर्ष 1990-91 में एजेंसी सेवाओं के कारण होने वाले कार्यकारी व्यय की विभाग द्वारा वसूली इस प्रकार थी:

(करोड़ रुपयों में)

बचत बैंक एवं बचत प्रमाण पत्र	247.46
डाक जीवन बीमा	10.79
रेलवे पेंशन का भुगतान	0.66
कोयला खनिक/ईपीएफ पेंशन	2.49
सीमा शुल्क वसूली	11.92
सेना पेंशन	0.16
अन्य	2.28
टेलीग्राफ शेयर	40.26
जोड़	316.02

पूंजीगत व्यय

वर्ष में नियत परिसंपत्ति पर सकल परिव्यय 31.48 करोड़ रुपये था जिसमें से 85.48% भूमि एवं भवन पर तथा 14.52% उपकरण और संयंत्र एवं अन्य के ऊपर व्यय हुआ था। वर्ष के अंत में नियत परिसंपत्ति पर पूंजीगत परिव्यय 424.82 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था। वर्ष के अंत तक शुद्ध प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के लिए सामान्य राजस्व द्वारा 346.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

मानव संसाधन

मानव शक्ति

इस विभाग के कार्मिक ही भारतीय डाक प्रणाली के सबसे बड़े संसाधन रहे हैं। 31.3.91 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5.92 लाख थी इनमें से 2.99 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं, जिनका बहुत बड़ा भाग गांवों में डाक सेवाएं प्रदान करता है।

पोस्टल स्टाफ कालिज

पोस्टल स्टाफ कालिज भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक-तार वित्त एवं लेखा सेवा के सीधी भर्ती द्वारा आए अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करता है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेमीनार, कार्यशाला, प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय विकास कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। पोस्टल स्टाफ कालिज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर सार्क देशों के अधिकारियों सहित विभिन्न काडरों के 107 अधिकारियों ने भाग लिया।

पोस्टल स्टाफ कालिज 16.4.90 से गाजियाबाद स्थित अपने नवनिर्मित भवन में चला गया था और उसके प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लाकों ने 16.4.90 से ही कार्य आरम्भ कर दिया था। हास्टल ब्लाक भी अक्तूबर 1990 में पूरा हो गया और तब से सभी सेवाकालीन और प्रवेश प्रशिक्षणार्थी पोस्टल स्टाफ कालिज के हास्टल ब्लाक में रह रहे हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 के दौरान पोस्टल स्टाफ कालिज, गाजियाबाद ने भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक-तार वित्त एवं लेखा परिवीक्षार्थियों के लिए सामान्य प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नालिखित पाठ्क्रम/सत्र आयोजित किए हैं :-

(1) 22.10.90 से 1.11.90 तक डाक अधिकारियों के लिए प्रबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(2) 4-10 दिसम्बर, 1990 तक ई एम एस को लोकप्रिय बनाने के लिये सार्क पाठ्यक्रम
(3) 18-28 फरवरी, 1991 तक प्रशासकीय विकास कार्यक्रम

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

डाक सेवा ग्रुप 'ख' के अधिकारियों सहित प्रचालन और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए इस समय 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र दरंभगा, मदुराई, मैसूर, सहारनपुर और बड़ोदरा में स्थित हैं। वर्ष 1990-91 में कुल मिलाकर लगभग 14800 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 1990-91 में लगभग सभी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया गया जिनमें विभाग के नए नियमों/अनुदेशों, मशीनीकरण, कर्मचारियों के जनता के साथ व्यवहार संबंधी पहलुओं आदि पर जोर दिया गया।

उच्चतर कार्य निष्पादन को मान्यता

विभाग ने निम्नलिखित कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए 'मेघदूत' पुरस्कार प्रदान किए -

1. श्री भावन कुमार, ईडी तार संदेशवाहक, पंजाब।
2. श्री जे. एम. राणा, ईडीडी ए, गुजरात।
3. श्री चन्देश्वर पासवान, पोस्टमैन, बिहार।
4. श्री रेलू राम, मेल ओवरसियर, हिमाचल प्रदेश।

5. श्री सोहन सिंह, एम वी मैकेनिक, दिल्ली।
6. श्री के. एस. थापा, जीप ड्राइवर, हिमाचल प्रदेश।
7. श्री चम्पाराम, विभागीय मेल रनर, हिमाचल प्रदेश।
8. श्री बन्त सिंह, एल एस जी, एस पी एम, पंजाब.
9. श्री आर. एस. कश्यप, एपीएम, एलएसजी, हिमाचल प्रदेश।
10. श्री सी. डी. मोहन्ती, एल एस जी, सहायक आर एमएस, उड़ीसा।
11. श्री एस. सी. पटयाल, एस डी आई (डाक), हिमाचल प्रदेश।
12. श्रीमती विजयलक्ष्मी के. नायर, एलएस जी, सुपरवाइजर, महाराष्ट्र।

स्टाफ कल्याण

डाक सेवाएं कर्मचारी कल्याण बोर्ड संचार मंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। इस बोर्ड का उद्देश्य इस विभाग के कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं एवं कल्याण, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित करना, आयोजित करना तथा उन पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। इस बोर्ड का वित्तीय संसाधन सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान है। इसके अतिरिक्त स्टॉफ द्वारा स्वैच्छिक अंशदान खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा धन एकत्र करने का कार्य अधीनस्थ संगठनों द्वारा किया जाता है।

कल्याण बोर्ड इस निधि का उपयोग खेल-कूद, कम्युनिटी सेन्टर, मनोरंजन क्लबों आदि गतिविधियों के लिए बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक विपदाओं में वित्तीय सहायता देना, शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, भ्रमण के लिए आर्थिक सहायता देना विकलांग स्टाफ एवं बच्चों, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शिशुगृहों को अनुदान देने के लिए करता है। वर्ष 1990-91 के दौरान 90 लाख रुपये कल्याण गतिविधियों पर खर्च किए गए।

अवकाश गृह

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान जम्मू, पुरी और कन्याकुमारी में तीन नए अवकाश गृह खोले गए। विभाग अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों के लाभ के लिए निम्नलिखित स्थानों पर अवकाश गृह पहले से चला रहा है :- तिरुपति (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी एवं काजीरंगा (असम), राजगीर, देवोगाह (बिहार), द्वारका (गुजरात), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), त्रिवेन्द्रम (केरल), मैथन (महाराष्ट्र), शिलौंग (मेघालय), गोपालपुर (उड़ीसा), उदयपुर (राजस्थान), अगरतला (त्रिपुरा), मसूरी (उ.प्र.), और दीघा और डायमंड बंदरगाह (पश्चिम बंगाल)।

खेल-कूद

वर्ष के दौरान बॉलीबाल, टेबिल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडीबिल्डिंग, एक्वैटिक एथेलैटिक एवं साइक्लिंग जैसे खेलों के लिए अखिल भारतीय डाक सेवा खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विभाग के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया।

राष्ट्रीय पुरस्कार

वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर इर्नाकुलम, केरल कार्यालय के कार्यालय सहायक श्री के.के. फजल मोहम्मद ने सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी के लिए वर्ष, 1991 का पुरस्कार प्राप्त किया।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी

विभाग ने अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के संबंध में सरकार के अनुदेशों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

विभाग अपने मुख्यालय और अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति

राजभाषा नीति के अनुपालन से संबंधित मामलों की देख-रेख एवं मार्गदर्शन करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियां सभी सर्किल मुख्यालयों, डिवीजनों और अधीनस्थ कार्यालयों में गठित की गई हैं।

आंतरिक कार्य अध्ययन

आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट ने निम्नलिखित अध्ययन किए और उन्हें अंतिम रूप दिया :-

जन संपर्क निरीक्षक (डाक) के पद स्वीकृति कराने के लिए मानदंड।

डाकघरों में फ्रेंकिंग मशीनें।

मेल मोटर सेवा यूनिटों में चार्ज हैंडो का अध्ययन एवं जॉब मूल्यांकन तथा कुशल कारीगरों का वर्गीकरण।

फार्मों की पुनरीक्षा।

डाकघरों में किसान विकास पत्रों की बिक्री से संबंधित स्टाफ के लिए मानदंड।

कार्य-प्रगति
(अप्रैल-दिसम्बर 1991)

नेटवर्क का विस्तार

डाक प्रचालन के विस्तार और विकास दोनों पर बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार जारी रहा। गहन मॉनीटरिंग द्वारा ग्रामीण डाकघरों की दक्षता बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए। इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए डाकघरों की कुल संख्या 446 थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा निर्मित और सरकार द्वारा स्वीकृत डाकघर खोलने के नए मानदंड लागू किए गए।

स्पीड पोस्ट

उपयुक्त प्रचार-प्रसार और पणन तकनीकों द्वारा स्पीड पोस्ट को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। फरीदाबाद स्थित एक्सटेंशन काउंटर को 1 नवम्बर, 1991 से पूर्ण अधिकार प्राप्त स्पीड पोस्ट केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान देश में प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के तहत 144 युग्म स्टेशन खोले गये। पहली अप्रैल, 1991 से मलावी, साइप्रस, कनाडा, इथोपिया, न्यूजीलैंड और सूडान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरु की गईं।

आधुनिकीकरण

डाक प्रचालनों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में ऑनलाइन बचत बैंक प्रचालनों के लिए साफ्टवेयर के विकास पर प्रगति हुई। इसे नेशनल इनफॉरमैटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग करने वाला पहला उप डाकघर इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर, नई दिल्ली था। इसमें 1 अप्रैल, 1991 से इसका उपयोग किया जाने लगा। बाद में दिल्ली सर्किल के छः अन्य प्रधान डाकघरों में बचत बैंक प्रचालनों के इसी प्रकार के कम्प्यूटर लगाए गए। इसके अलावा बम्बई के लिए स्वचालित मशीनी छंटाई संयत्र उपलब्ध कराने संबंधी मूल कार्य इस अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया जिसके लिए पहली जनवरी, 1992 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

मेल बॉक्स योजना

डाक विभाग बहुमंजिली इमारतों में डाक के वितरण में कठिनाईयां महसूस करता रहा है क्योंकि इनकी संख्या न केवल बड़े शहरों में बल्कि अन्य शहरों में भी बढ़ रही है। डाक कर्मचारियों की सहायता करने और वितरण में विलम्ब से बचने के लिए 29 मई, 1991 को एक सांविधानिक आदेश जारी किया गया कि भूतल पर रहने वाले लोगों को छोड़कर अन्य तलों पर रहने वाले लोग भूतल पर एक डाक बॉक्स की व्यवस्था करें।

बीमा सीमा

14 सितम्बर, 1991 से बीमा की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ से संबंध

अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ के डाक अध्ययनों के लिए सलाहकार समिति के सदस्य तथा एशियाई प्रशान्त डाक संघ (एपीपीयू) के सदस्य के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय डाक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इन दोनों संघों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है,जैसे-सी सी पी एस/7 की समिति का अध्यक्ष और ए पी पी यू की तकनीकी सहयोग और सहायता पर स्थाई समिति का अध्यक्ष।

अप्रैल, 1991 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क अध्ययन दौरे में भारत की ओर से एक सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। जून 1991 में श्री लंका में आयोजित सार्क सेमिनार में भाग लेने के लिए विभाग के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था और डाक सेवाओं की तकनीकी समिति को भी जून 1991 में काठमांडू भेजा गया था। भारत ने विश्व डाक संघ सदस्य देशों के लिए 18 नवम्बर, 1991 से 14 दिसम्बर, 1991 तक वरिष्ठ डाक प्रबंध पाठ्यक्रम आयोजित किया। पाठ्यक्रम में 13 देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया एक अधिकारी ने एशियन पैसिफिक पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर बैंकाक में 3 जून, 1991 से 15 जून, 1991 तक डाक प्रबंध पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस अवधि के दौरान यू पी यू द्वारा यू एस एस तथा जर्मनी के लिए प्रायोजित कंसलटेंसी मिशन के अंतर्गत अधिकारियों को भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया था।

फिलैटली

इस अवधि के दौरान भारत ने 4 से 13 अगस्त, 1991 तक बैंकाक में 8 से 29 अगस्त, 1991 तक पेरू में तथा 21 से 25 अक्टूबर, 1991 तक वॉन में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिलैटलिक प्रदर्शनियों में भाग लिया। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश तथा बिहार सर्किलों द्वारा सर्किल स्तर की दो प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया था कुल 46 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए।

परिसर

भवन गतिविधियों पर बराबर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवधि के दौरान 33 कार्यालय भवन तथा 65 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष के आरम्भ में 24 कार्यालय भवन तथा 93 स्टाफ क्वार्टरों पर निर्माण कार्य चल रहा था। उसे पूरा किया गया।

विशेष भर्ती अभियान

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पहले से खाली चले आ रहे आरक्षित पदों को भरने के लिए वर्ष 1991 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 2136 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई की गई थी इनमें से 1562 रिक्त पदों को भरा जा चुका है।

पोस्टमास्टर जनरलों की बैठक

20 तथा 21 दिसम्बर, 1991 को सर्किल अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई उप समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए।

राजभाषा

पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान 16 सितम्बर, 1991 से 20 सितम्बर, 1991 तक विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विभाग ने प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की जैसे डाक विभाग राजभाषा शील्ड। अनेक कर्मचारियों को, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में उनके सहयोग के लिए नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिए गए।

PREAMBLE

THE POST — STRUCTURE & FEATURES

The Post in India is a basic public service of collecting, conveying and delivering mail from one person to another, governed by a statute which, while giving to the Government the authority, limits the fee that it may collect, and, while defining the nature of the services, imposes limits on the restrictions that it may lay down. The statute is protective of the Government's exclusive privilege with letters, as well as its liability, and is enabling for the rest of the mail.

The Post also conveys remittances of money from one person to another, and carries out, besides, a number of functions for the society, on behalf of other Departments of Government.

OVERVIEW

The last report emphasised on the obvious need of technology so as to counter the competition from private couriers as well as to step up the efficiency of the Indian postal system. Even though the Indian Post lagged behind other countries in the induction of technology, the imperative requirement of using technology has been realised and number of measures were taken to introduce technology in various areas. These measures were also in line with the recommendations of the Expert Committee on Excellence in Postal Services, which made the induction of technology as central theme of the report.

Big Push in Technology

There had been a period of lull in the technology induction in the earlier years. By and large the efforts made were sporadic and unsystematic. However, in the year 1991-92, definite objectives in the field of technology were drawn up. The advice of the experts of the Department of Electronics was made available. In essence, this year may be said to be a year of breakthrough in technology. The Steering Group set up by the Minister of State for Communications under the chairmanship of Dr. Sam Pitroda with Secretary (Posts), Secretary (Electronics), Director-General, NIC and Members of the Postal Services Board continued to meet in order to monitor the progress in the induction of technology. These regular meetings helped to speed up and remove the possible hurdles.

Thrust Areas

The thrust areas of mechanisation and modernisation in the Department of Posts can be conveniently divided into following broad classifications:

- Computerisation
- Networking through satellite for introduction of Money Transfer Service.
- Mechanised sorting
- Stamps, seals, postal machines and equipment.

Post Office Computerisation

This basically consists of multi-purpose counter machines to increase profit and customer satisfaction. It also consists of central consolidation of accounts, inventory control of accountable articles and valuable instruments such as stamps, postal orders, certificates etc. During 1990-91, 102 multi-purpose counter machines were installed. Based on this experience, it has been decided to progress further by installing more machines. Along with the computerisation, computerisation of administrative offices will also be taken up during 1992-93. Savings Bank computerisation also received a fillip during the last financial year. Based on these results, it is proposed to speed up introduction of Savings Bank computers in other post offices in phases. For two international speed posts centres, tracing and tracking equipment was procured. It is proposed to instal similar machines in 12 domestic speed post centres also during the year 1992-93. The progress in computerisation in this way is likely to lead to optimum efficiency in the post offices and lead to increased customer satisfaction.

Satellite Money Order Service

The Department has plans to instal 75 micro earth stations (also called Very Small Aperture Terminals – VSATs) to transmit money order advices via satellite communications. This will significantly reduce the transit time of money orders. It will particularly help those members of the society who are sending money orders to their families from cities to remote or hilly areas. This is bound to improve efficiency and the cost will also be met within the existing tariff.

Mechanised Sorting

Recently an agreement was signed between Department of Posts and Bell Telephone Manufacturing Company,

Antwerp, Belgium. Under this agreement automatic integrated mail processing system will be installed at Bombay. This equipment consists of two Letter Sorting Machines and 30 Manual Coding Desks in six suites. The operator on each coding desk can achieve a high speed of letters in coding. The coded mail will be automatically sorted by the Letter Sorting Machine at a high speed. This equipment is expected to reduce the sorting bottleneck at Bombay. It will also provide a superior information base for manpower planning.

Stamps, Seals and Postal Machines

Department has placed orders for manufacture of machine-engraved hardened steel stamps for impressing of postmarks on the pieces of mail. These are expected to improve the quality of stamping. The Department is also having a dialogue with manufacturer for better quality of stamp cancellation machines and electronic franking machines.

Expansion of Network

The question of review of norms for opening of post offices during the 8th Five-Year Plan was under consideration. The National Institute of Rural Development, Hyderabad, was asked to conduct the study. Based on their recommendations, the new norms have now been finalised. These new norms are more liberal in the case of hilly and backward areas. These norms have since been approved by the Government and these are being adopted for purposes of rural network expansion. However, the time has come to evaluate the postal expansion programme carried out so far to see how effective this has been in leading to rural development and also to close down those post offices which have been proving to be chronically uneconomical and not conforming to the prescribed norms.

Washington General Action Plan

The Congress of the Universal Postal Union finalised the Washington General Action Plan, considered to be a vital document for all the postal administrations. A key orientation of the Plan related to meeting the needs of the customers. Towards this end, a Marketing Organisation was set up at the headquarters. This was followed up by establishment of marketing cells in the various circles. The functioning of the marketing cells and their responsiveness to customer requirements would, in essence, shape the postal services in future, especially the Speed Post. During the year 1991-92, Speed Post registered substantial progress, thanks to publicity and improved marketing techniques. However, it is imperative at this time to decide upon a particular structure for the Speed Post Organisation which will ensure functional flexibility on commercial lines. This alone can help Speed Post to overcome the stiff competition of the private couriers. The Department will be addressing itself to this task in future.

Philately

In the last Report, it was indicated that the Department was looking for printing of stamps by outside printers as well as for introduction of deluxe stationery. Efforts in this direction did bear fruit and the Department has since placed orders for printing of stamps of a higher quality. Special emphasis is being laid for improving the colour scheme of the stamp so that it is attractive. With these measures, the problems on account of the limitations of the old machinery at Nasik Security Press can be said to have been overcome. The question of undertaking printing of stamps for other countries is engaging the attention of the Department and success in this area would lead to earning of substantial amount of foreign exchange for the country.

Deficit

In the year 1990-91, the net working expenditure was Rs. 1032.50 crores against which the revenue was Rs. 840.85 crores, thus the deficit being Rs. 191.65 crores as against Rs. 262.99 crores in the previous year. Since the cost of each item of service is generally much greater than the actual expenditure on it, the Indian postal system has been facing a difficult situation. The tariff revision could be one of the measures to contain losses. However, it is also a double-edged weapon, i.e. when the tariff goes up, the traffic could come down as a result of elasticity of demand. The postal service is also looked upon as a social service and the tariff is not always fixed with the cost in view. The solution

apparently lies in structural improvements and modernisation which alone could bring down the deficit by improving efficiency and reducing costs.

Biennial Cadre Review

The last Report highlighted the expectations of the Unions and Associations who had been feeling that not enough was being done for the staff. The question of Second Time Bound Promotion for the staff who have completed 26 years of service had been under consideration. The Government have since approved this as part of a scheme of Biennial Cadre Review wherein the requirement of modernisation of postal services is also made a significant part. While the Biennial Cadre Review has been introduced, it remains to be seen as to what type of structural corrections would have to be applied so as to ensure a high level of efficiency and productivity coupled with modernisation of postal services. An important step to improve the lot of the Extra Departmental employees has been taken recently, i.e. the introduction of the Group Insurance Scheme.

Five-Year Plans

During the Seventh Five-Year Plan period from 1985-86 to 1989-90, as against an outlay of Rs. 195.80 crores, the actual expenditure was Rs. 176.67 crores, i.e. about 90% of the total outlay. The programmes for the Eighth Five-Year Plan have since been drawn up and the main emphasis of this Plan would be the technology thrust, while ensuring the continuation of the various programmes initiated during the Seventh Five-Year Plan. In order to ensure that there are no slippages in the Eighth Five-Year Plan, specific projects will be handled by Project Managers who will closely monitor the progress till the end. Success of the Eighth Five-Year Plan would be largely dependent upon the performance of these Project Managers.

Future Programmes

In order to ensure that the Department is revitalised to meet the rapidly changing environment, the need for a compact and efficient organisation and the changes required for achieving it was keenly felt. It was also considered that the management should be accountable and to this extent the performance of circles and regions should be monitored. Benchmarks were to be suggested for selecting the best Circle to receive the Rolling Trophy to be instituted. In this context, in the Postmasters General's Meet in December, 1991, sub-committees were formed to discuss groups of inter-related issues and to make recommendatiosn on them. These sub-committees handled performance standards in mail transmission and delivery, management of counter transactions and enhancement of customer satisfaction including the Consumer Protection Act, organisational structure of the Civil Wing, revision of qualifications for promotion to the cadres of Postal Assistant, Postmen etc., inspection procedures and preventive vigilance, restructuring of the postal organisation, performance indicators for assessing the best Circle and resources generation. The recommenations of these sub-committees were considered during the conference and the decisions taken on these subjects would form the basis for drawing up future programmes of the Department.

In short, the year 1990-91 can be looked upon as a turning point in the development of the postal services in the country. The creative and innovative responses have been framed to meet the new challenges and far-reaching initiatives started. The success of the Department will be in the field of technological assimilation coupled with improved management to meet the customer requirements. The efforts of the Department will be to stem the falling productivity and to introduce structural corrections to optimise efficiency.

ORGANISATION

The Department of Post , created in January 1985 after the bifurcation of the erstwhile Posts and Telegraphs Department, is a part of the Ministry of Communications. During the period under review, the Ministry of Communications was under the charge of Dr. Sanjay Singh, Minister of State for Communications. Currently the Ministry of Communications is under the charge of Shri Rajesh Pilot, Minister of State for Communiations. Shri P.V. Rangayya Naidu is presently the Deputy Minister for Communiations.

Headquarters

The management of the Department vests in the Postal Services Board composed of four Members and the Chairman. Secretary, Department of Post is the Chairman of the Board. The Members hold the portfolios of Operations, Development, Personnel and Finance. The Board has a Secretary.

Secretary, Department of Post is also the Director General, Post

The Board is assisted by Deputy Directors General.

Circles

The Department's operational responsibilities are borne by the 19 Circles into which the country is divided. A Circle comprises one or more States/Union Territories. Circle is headed by Chief Postmaster General or Postmaster General. 16 Circles which are headed by Chief Postmasters General are divided into regions composed of a group of Postal Divisions, or have a Postmaster-General to support. Of these, posts of Chief Postmaster General of 7 Circles is in the grade of Rs. 7300-7600 – Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. The Regional Mail Planning units at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras are also under the controllers of the level of the Postmaster General for bringing better professionalism to this function. There are also functional Divisions and units like Mail Division, Stores Depot, Stamp Depot and Mail Motor in a Circle.

Post Offices fall in the category of Head, Sub and Branch Post Offices. Branch Post Offices are Extra Departmental Post Offices and Sub Post Offices, mostly, are Departmental Post Offices. Head Post Offices are graded into five categories according to their size, the biggest being the Presidency Post Offices of Bombay, Calcutta and Madras.

The Army Postal Service headed by a Major General, designated Additional Director General, Army Postal Service, is reckoned as a Postal Circle.

Positions

As on 31st March, 1991, the Postal Services Board consisted of Shri Kailash Prakash, Secretary (Posts) and Director General, Posts, Shri S. Krishnan, Member (Finance), Shri S.P. Ghulati, Member (Operations), Shri M.S. Paulrajan, Member (Development) and Shri P.R. Rao, Member (Personnel). Shri V.S. Ailawadi was Secretary, Postal Services Board.

Currently, Shri S.P. Ghulati is the Secretary of the Department of Posts with effect from 17th December, 1991. At present Shri L.D. Bonnell is the Member (Personnel) and Shri C.P. Thomas is looking after the charge of Member (Development). Shri S.K.N. Nair, Member (Finance), Telecommunication is holding additional charge of the post of Member (Finance), Department of Posts. Shri Y.L. Rajwade is now the Secretary of the Postal Services Board.

Relations With UPU

Universal Postal Union, a specialised agency of United Nations, is the international organisation of Postal Administrations. During the year, it had a membership of 170 administrations. India continued to play a leading role in the International postal affairs as a member of Consultative Council for Postal Study of the UPU as also a member of the Asian Pacific Postal Union (APPU). In both these Unions, India holds coveted positions, namely as Chairman of Committee 7 of the CCPS and the Chairman of Standing Committee on Technical Co-operation and Assistance of APPU.

The Sixth Congress of APPU was held at Rotorua in New Zealand from November 25 to December 6, 1990. The Congress is the supreme body of the APPU and meets once in five years. The meeting is generally held within two years of the holding of the UPU Congress. It carries out functions like changing the rules and procedures relating to International Postal Service, draws up a study programme on technical, operational and economic issues concerning the postal services as also decides on the principles of technical co-operation policies in the region for the next five year period. A six member delegation led by Shri Kailash Prakash, Secretary, Department of Posts, attended the 6th APPU Congress. The other members of the delegation were S/Shri M.S. Paulrajan, Member (Development), S. Krishnan, Member (Finance), B.T. Menghani, Member (Personnel), N.K. Verma, Deputy Director General (International Relations) and Raghav Lal, Director (Savings Bank/ International Relations). India was unanimously elected as the Chairman of an important Committee of APPU, i.e. the Standing Committee on Technical Co-operation and Assistance. India was also invited to chair the discussion on implementation of Washington General Action Plan in APPU region.

A two member Indian delegation led by Shri Kailash Prakash, Secretary, Department of Posts, also attended the annual session of CCPS in October, 1990. India as Chairman of Committee 7 of CCPS is also a member of the Steering Committee of CCPS. This Committee deliberates on progress of various studies being conducted by CCPS and guides its future course.

Other International Meetings

India also attended the following international meetings: One member Indian delegation participated in the Philatelic Exhibition held in Moscow, USSR in August 1990. One member Indian delegation attended the World Stamp Exhibition Singapex in Singapore in August 1990. Shri N.K. Verma, DDG (SBO) visited France to study the computerised Savings Bank Accounting and working of the GIRO system. He also participated in the 16th World Congress at the International Savings Bank Institute in Rome. India attended the 9th meeting of the SAARC Technical Committee on Postal Services held at Male in June, 1990.

POSTAL OPERATIONS

Introduction

Postal Operation is often perceived as a single function of delivering the letters from one end to another. As a matter of fact, it is a chain of multifarious interrelated functions. And the success of this operation is often dependent on the efficiency of other agencies in the Transportation Sector – such as Airlines, Railways, etc. Post also performs functions for other Ministries/Departments e.g. Savings Bank and Postal Life Insurance, known as Agency functions.

Expansion of Postal Network

The Postal network as on March 31, 1991 comprised 148,719 post offices of which 132,646 were rural and the remaining 16,073 urban. In the year 1990-91 alone, 1,476 rural post offices were sanctioned. Each post office serves, on an average, an area of 22.10 sq. kms. and a population of 4607. With this level of development, the country is well within the norms adopted by the Universal Postal Union (UPU) that there should be one post office to serve on an average either an area of between 20 to 40 sq. kms. or 3000 to 6000 inhabitants. There were 5,20,074 letter boxes in the country, out of which 4,36,667 were in rural areas and 83,407 in urban areas.

Mail was handled by a network of 548 mail offices. There are, also six offices of international mail exchange at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Cochin and Patna. Mail is transported by air, by road and by trains.

Number of Post Offices

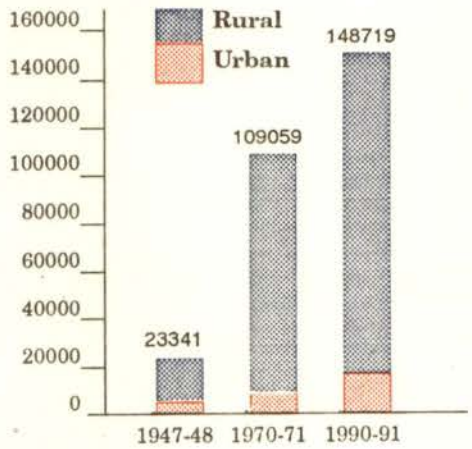

Services

The Post renders

Mail Services,
namely
Letter,
consisting of:
envelopes,
letter cards,
postcards

Book Packet

Newspaper Packet

Parcel

Classified as:
Ordinary Mail
Posting Certified-
Ordinary Mail
Recorded Delivery
Registration
Value-payable
Insurance
SpeedPost

Money Transfer Services,
namely
Money Order
Postal Order

Other Services,
namely
Saving Bank
Postal Life Insurance
Telegraph
Telephone Public call Offices
Telephone Revenue Collection

Postal Traffic Since 1981-82
(Adjusted to Revenue)

(In Millions)

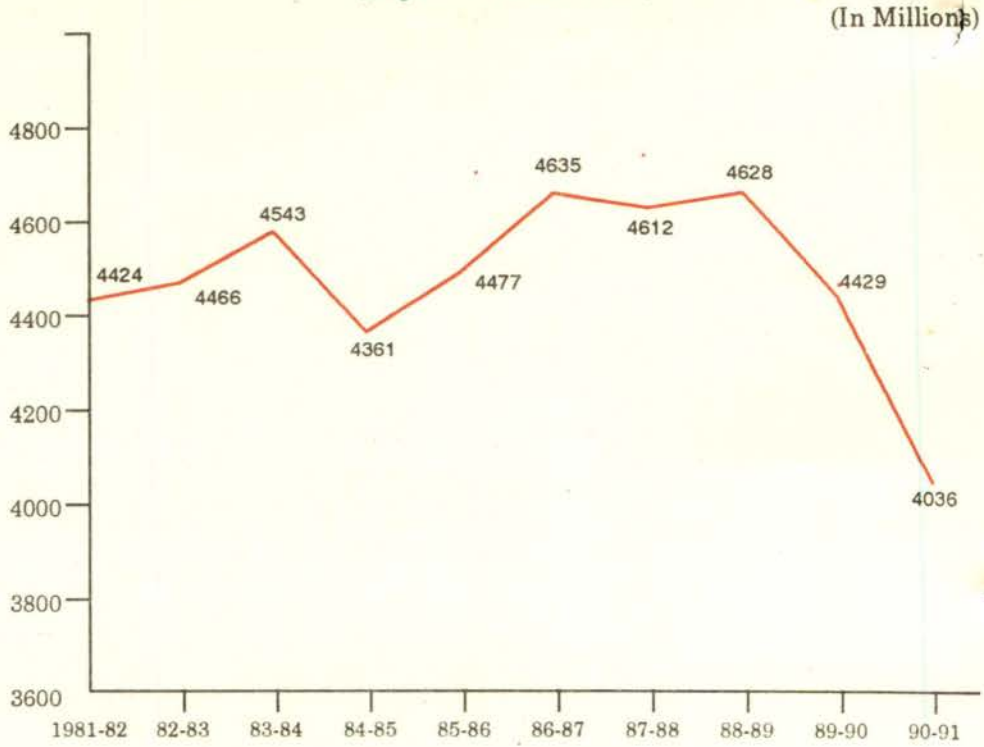

Articlewise Postal Traffic

(In Millions)

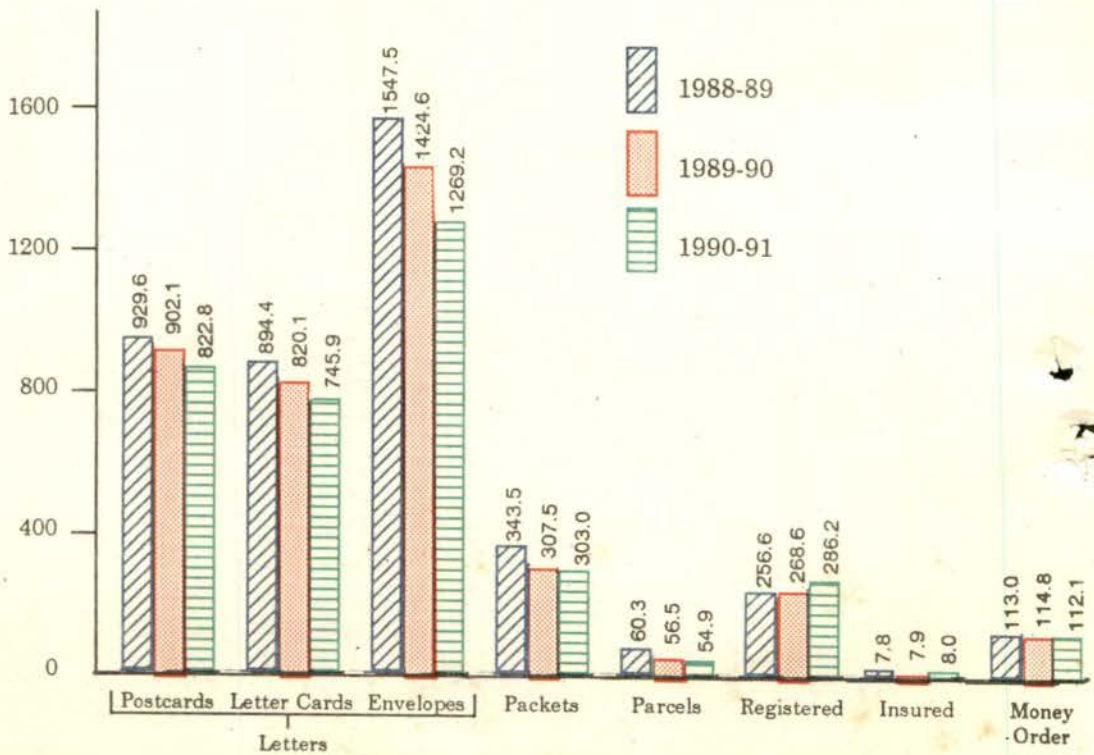

Mail Volume

Domestic unregistered mail handled during the year numbered 3287 million consisting of 2778 million letters, 476 million packets and 33 million parcels. Domestic registered mail numbered 311 million. Registered mail increased in number in 1990-91 over the previous year while the unregistered mail declined.

The Post conveyed 105.8 million remittances of money aggregating Rs. 29372 million during the year by way of money order. Remittances by way of Postal Orders totalled Rs. 236.2 million.

Speed Post Traffic
(In Thousands)

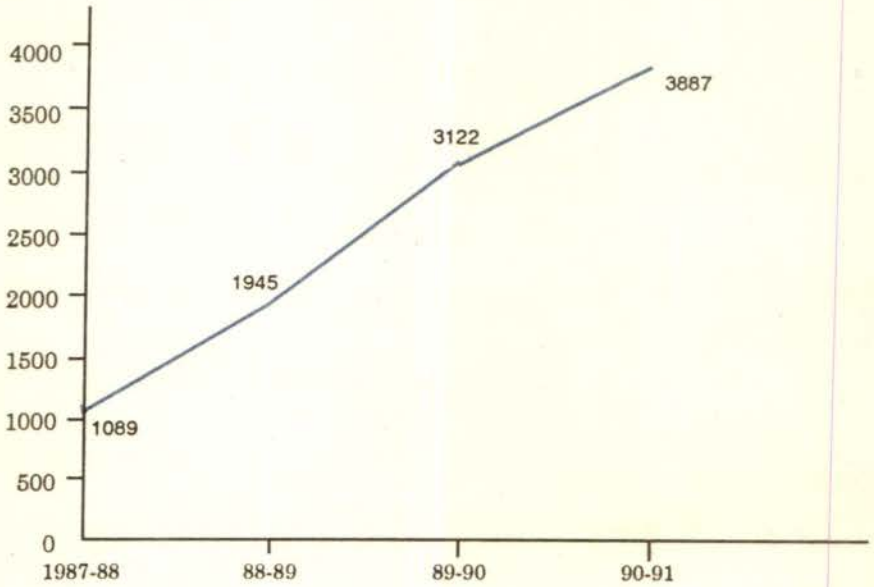

Speed Post

There are 60 centres for Speed Post. During the period from 1.4.90 to 31.3.91 the following centres were opened in the country:

Trichur	from	4.6.1990
Jalandhar	from	16.8.1990
Ludhiana	from	12.10.1990

Point-to-point Speed Post Service and Customer-specific contractual Speed Post service and speed post pick-up service have been introduced with effect from 12.10.1990. Speed Post tariff has been rationalised with effect from 1.12.1990. Incentive scheme for booking and delivery of Speed post articles has been revised with effect from 1.11.1990.

During the period 1.4.1990 to 31.3.1991, International Speed Post links were established with the following countries:

Indonesia	from	1.5.1990
Saudi Arabia	from	1.5.1990
People's Republic of China	from	1.9.1990
Sri Lanka	from	1.9.1990
Maldives	from	11.9.1990

During the same period, three International Speed Post Booking Centres were opened at Trichur, Jalandhar and Ludhiana.

Technology Induction

For better services to the public, the Research and Development Wing of the Department has laid its basic emphasis on two aspects: (i) Mail Mechanisation and (ii) Counter-Mechanisation. The secret of quicker delivery of mail lies in quicker mail sorting. In the major metro cities of Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, Ahmedabad, Hyderabad and Bangalore, the volume of mail to be sorted per day exceeds more than 2 millions. In addition to the volume of mail, the department faces the problem of peak hours. The ever increasing mail traffic has rather exposed the weaknesses of manual sorting system. The only answer to this is mechanisation of mail sorting. For thispurpose, to start with, the project at Bombay has been identified as pilot project, which will be followed by similar machines in other metros.

Counter-mechanisation has been another thrust area. To provide multiple transactions at one counter to the public, on an experimental measure, 102 personal computer based multi-purpose counter machines have been installed in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Ahmedabad, Bangalore and Lucknow. The performance of these equipments in various places is being monitored very closely.

The matter relating to improvement of stamp impression by obtaining machine-made stamps with hardened steel is also under consideration. This apart, the back office work like Management Information System, Head Post Office, Accounting System etc. are also being considered specially with a computer networking system.

Mail Motor Services

The Department Mail Motor Service functioned in 90 stations in the country during the year 1990-91. During the year under review, 158 new vehicles were purchased to replace the condemned vehicles in order to improve and maintain the efficiency and quick transmission of mails. The total fleet strength of the Mail Motor Vehicles at the end of 1990-91 was 1103.

Philately

Forty one Commemorative/Special postage stamps were issued during 1990-91. One special stamp on Mahatma Gandhi in denomination of 100 p was issued during this period. 49 Philatelic Bureaux and 173 Philatelic-Counters were in existence as on 31.3.1991.

The following Circle level Philatelic Exhibitions were organised during this period:

Gujapex-90: At Ahmedabad for Gujarat Circle from 25.5.90 to 27.5.90.

Rajpex-90: At Jaipur for Rajasthan Circle from 23.8.90 to 26.8.90.

Chandipex-90: At Chandigarh for Haryana and Punjab Circles from 31.8.90 to 2.9.90.

Mappex-90: At Bhopal for M.P. Circle from 20.9.90 to 23.9.90.

Mahapex-90: At Bombay for Maharashtra Circle from 21.9.90 to 24.9.90.

Tanapex-90: At Coimbatore for T.N. Circle from 4.10.90 to 7.10.90.

Karnapex-90: At Bangalore for Karnataka Circle from 12.10.90 to 14.10.90.

Uphlipex-90: At Lucknow for U.P. Circle from 26.11.90 to 29.11.90.

Dakiana: At Delhi for Delhi Circle from 31.1.91 to 3.2.1991.

The Department participated in the following international Philatelic Exhibitions:

Singpex-90: At Singapore from 16.8.90 to 19.8.90.

New Zealand-90: At Auckland from 24.8.90 to 2.9.90.

Vien-90: At Vienna from 29.8.90 to 2.9.90.

Sportiphilex-90: At Beijing from 22.9.90 to 3.10.90.

Philatelic Exhibitions were organised in Moscow (USSR) and New Delhi from 16.8.90 to 18.8.90 simultanoeusly on reciprocal basis.

Agency Services

Post Office Savings Bank

Post Office Savings Bank continues to be the largest bank with 93.40 million accounts and a deposit of Rs. 177560 million.

Post Office Savings Bank runs the following schemes on behalf of the Ministry of Finance:-

Savings Accounts
Recurring Deposit Accounts
Time Deposit Accounts
National Savings Schen
Monthly Income Scheme
Public Provident Fund
Indira Vikas Patras
Kisan Vikas Patras
National Savings Certificates 8th Issue

Outstanding Balances in all forms of Savings including Certificates
(Millions of Rupees)

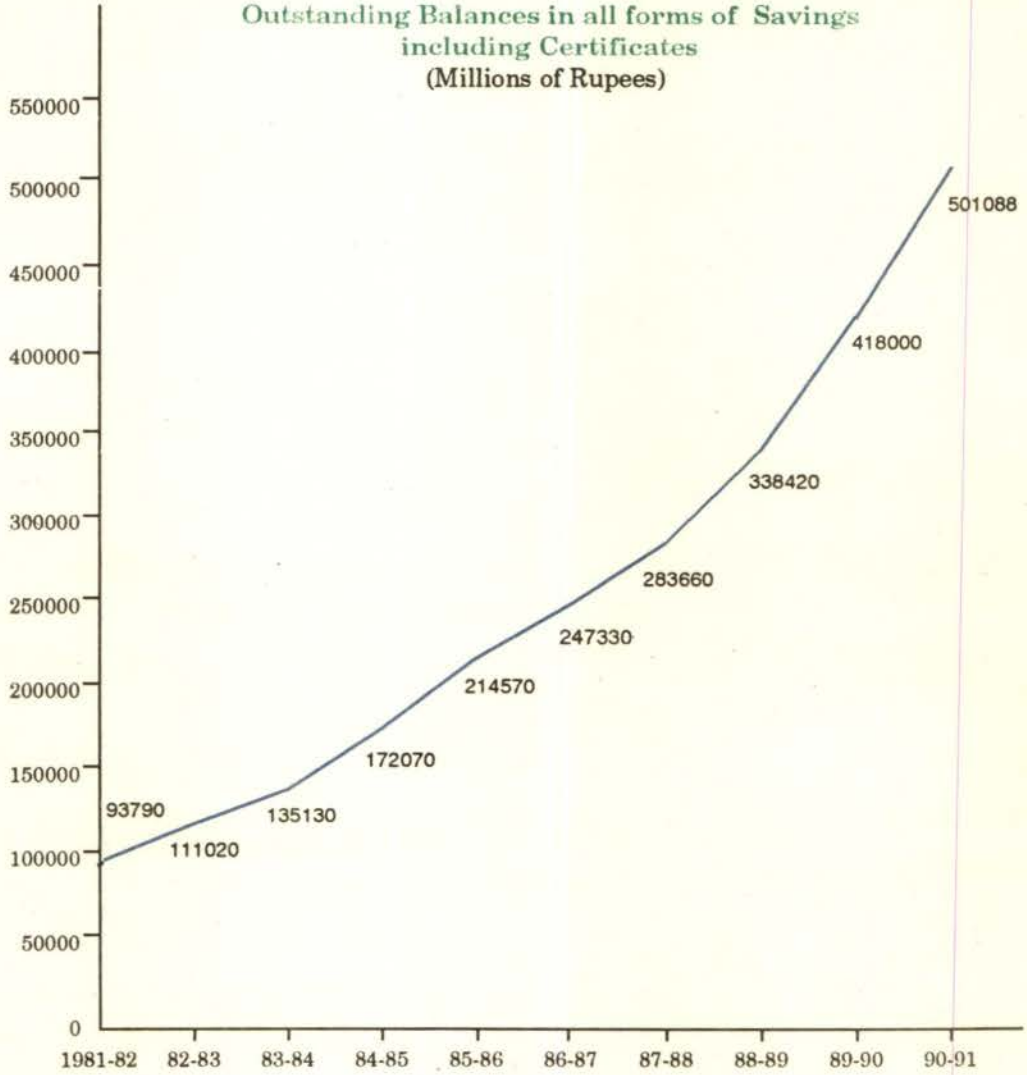

Postal Life Insurance

Postal Life Insurance offers the following four policies:

— Endowment Assurance
— Whole Life Assurance
— Convertible Whole Life Assurance
— Anticipated Endowment Assurance 15 years and 20 years

Bonus declared during the last four years is as follows:

	Whole Life	*Endowment Assurance*
	(per thousand sum assured per annum)	
1987-88	Rs. 78/-	Rs. 63/-
1988-89	Rs. 80/-	Rs. 65/-
1989-90	Rs. 83/-	Rs. 67/-
1990-91	Rs. 85/-	Rs. 70/-

In 1990-91 business rose to 16,91,754 policies for Rs. 2567.85 crores compared to

Total Number of Policies
(In Millions)

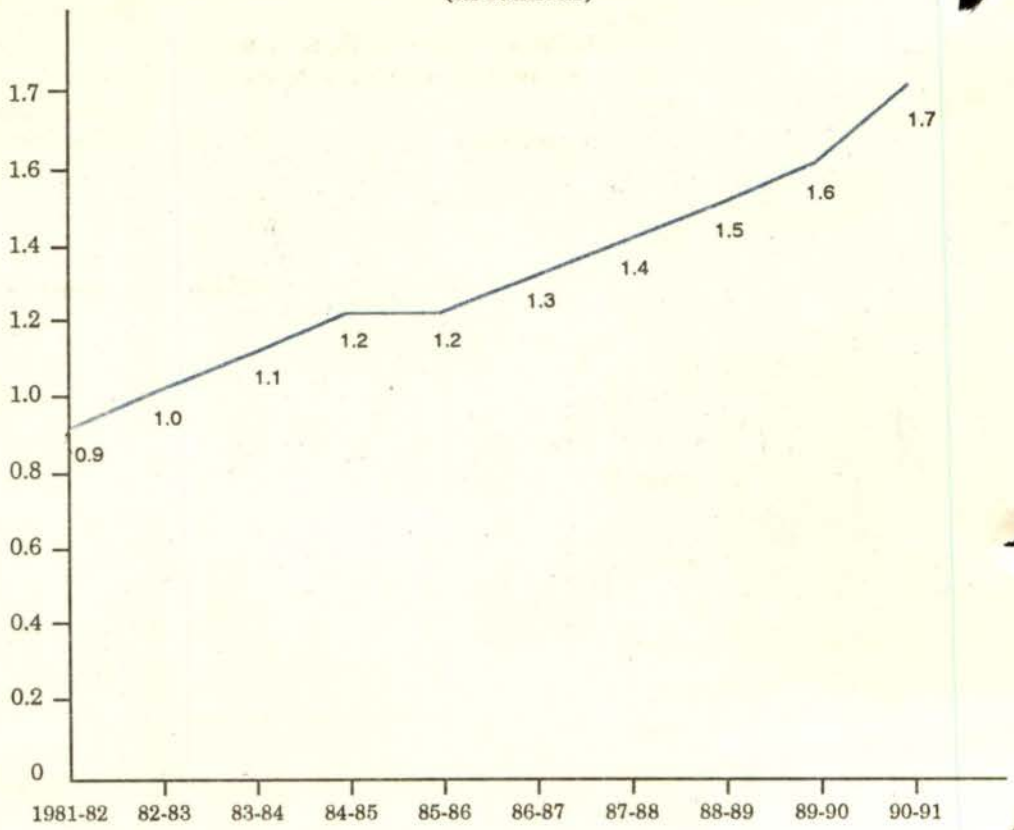

Total Sum Assured
(In Millions of Rupees)

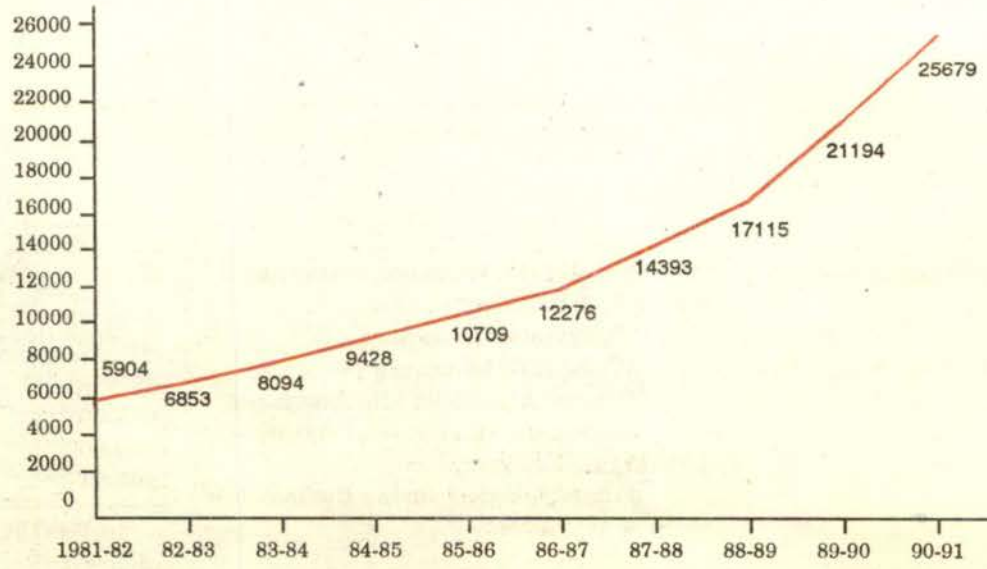

Life Insurance Fund
(In Millions of Rupees)

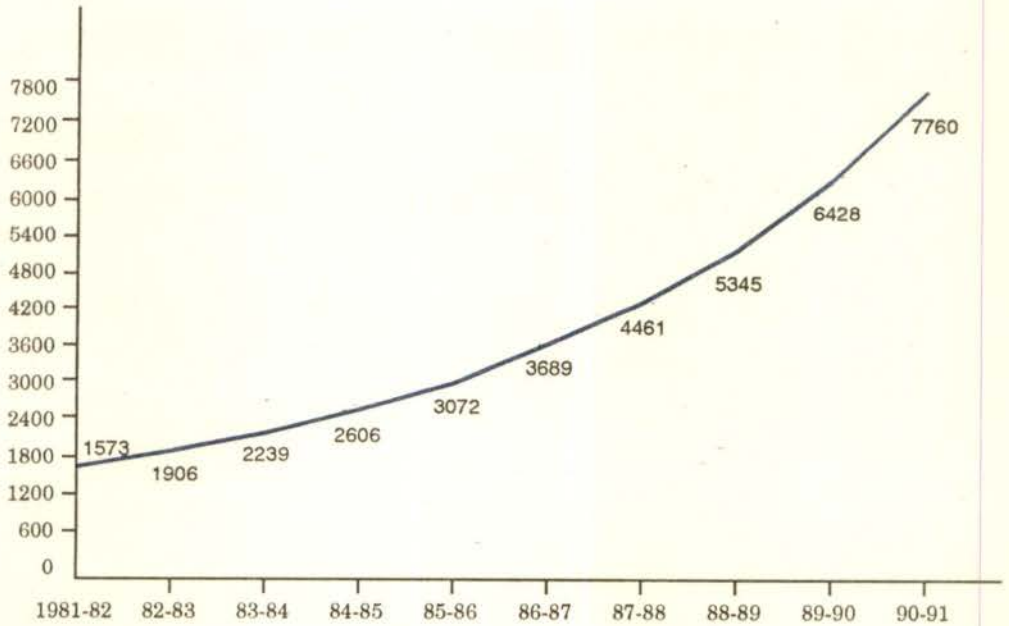

15,79,481 policies for Rs. 2119.40 crores in the previous year. Gujarat Circle leading the rest with 2,44,131 policies as on 31.3.1991. In 1990-91, new business of 1,56,358 policies were issued for Rs. 476.27 crores compared to 1,62,510 policies for Rs. 432.49 crores. Gujarat and Karnataka circle led the rest by 26219 and 20515 policies for Rs. 89.34 crores and Rs.53.06 crores respectively.

Customer Satisfaction

During the year under review i.e. 1990-91, 682599 complaints were received and enquired into as against 710597 in the year 1989-90. In 1990-91 the percentage of complaints to the total traffic handled is also marginally less i.e. 0.00461% against 0.00486% in the previous year.

Returned Letters

Department's 15 Returned Letter Offices, which ultimately process undelivered mail, handled 32.8 million pieces of mail during 1990-91. 53% of them were further improved in their address and delivered to the addressees. 27% were returned to the senders after ascertaining their addresses.

Postal Premises

The Department was able to enhance its building activity during the year to the extent of Rs. 28.03 crores and commence construction of 105 office buildings and 157 staff quarters as new projects besides completing construction of 91 office buildings and 105 staff quarters, which were on-going from the previous year. At the end of the year, construction of 192 office buildings and 395 staff quarters was in progress. For the year 1990-91, construction of 361 office buildings (including 52 works relating to extension of existing buildings) and 808 staff quarters was approved as new projects. The department invested Rs. 2.08 crores in acquiring land and 77 sites were acquired during the year.

POSTAL FINANCE

In the last five years from 1986-87, Postal Services have incurred an aggregate revenue deficit of Rs 1031.67 crores.

Year	*Deficit (Rs. in crores)*
1986-87	216.43
1987-88	190.87
1988-89	169.73
1989-90	262.99
1990-91	191.65

The total revenue during the year 1990-91 was Rs.840.85 crores, registering an increased receipt of Rs. 138.26 crores (i.e. about 19.7%) against the preceding year's receipts of Rs. 702.59 crores. This increase was mainly due to the upward revision of tariff rates of certain postal stationery with effect from June 11, 1990. The revenue realisation was 93.4% of the estimated revenue for the year, i.e. short by Rs. 59.15 crores.

The net working expenses of the year were Rs1032.50 crores as against the previous year's expenditure of Rs 965.58 crores (i.e. an increase of about 6.9%) and against the estimated expenditure of Rs. 1059.38 crores projected in R.E. 1990-91. The increase was mainly on account of higher staff cost, greater burden for pensionary charges, following a change in the procedure for accountal thereof and general price rise.

REVENUE AND EXPENDITURE 1990-91

(As compared to 1989-90)

(Rs. in crores)

Particulars	*1989-90*	*1990-91*	*Percentage change over the previous year*
REVENUE			
Sale of stamps	431.64	511.66	18.5
Postage realised in cash	133.65	173.18	29.6
Commission on account of money orders and Indian Postal Orders	105.55	110.46	4.7
Other receipts	31.75	45.55	43.5
TOTAL	702.59	840.85	19.7
EXPENDITURE			
General Administration	80.25	83.28	3.8
Operation	618.94	643.93	4.0
Agency Services	33.62	34.30	2.0
Others	232.77	270.99	16.4
TOTAL	965.58	1032.50	6.9

The gross expenditure in important categories is given below:

Pay and allowances, contingencies, interim relief and other items	952.05	1004.60	5.5
Pensionary charges	110.18	150.31	36.4
Accounts and Audit	28.99	30.88	6.5
Stamps and Postcards etc.	42.23	34.77	(–) 17.7
Stationery and Printing etc	18.93	23.41	23.7
Maintenance of assets etc.	7.12	1.49	(–) 79.1
Petty works	1.04	1.48	42.3
Conveyance of mails (Payment to Railways and Airmail Carriers)	58.07	55.92	(–) 3.7
TOTAL	1218.61	1302.86	6.9

POST CARD

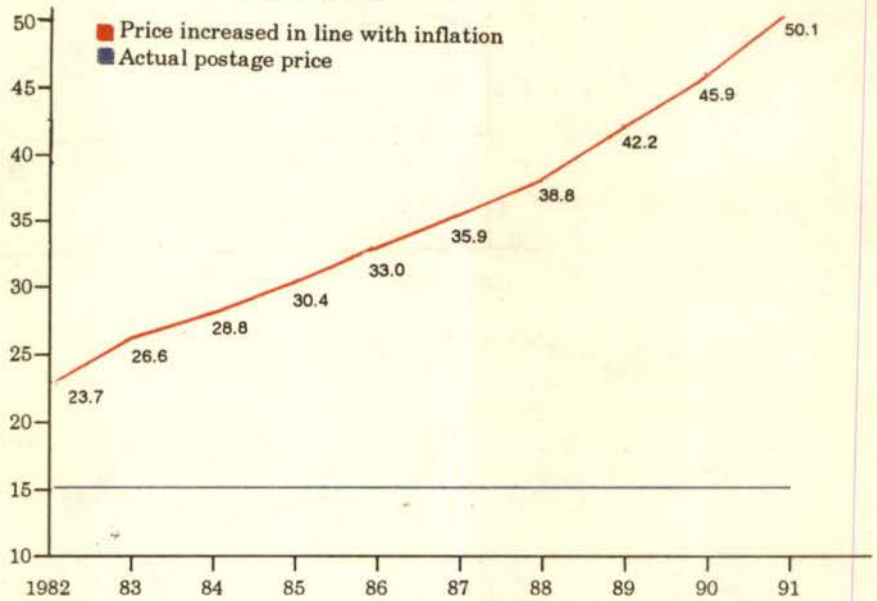

LETTER

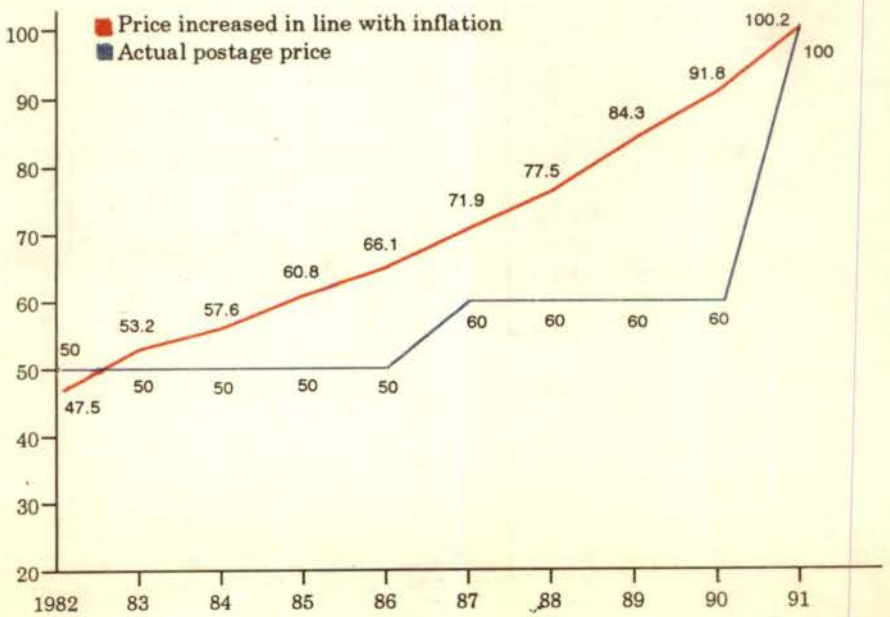

LETTER CARD

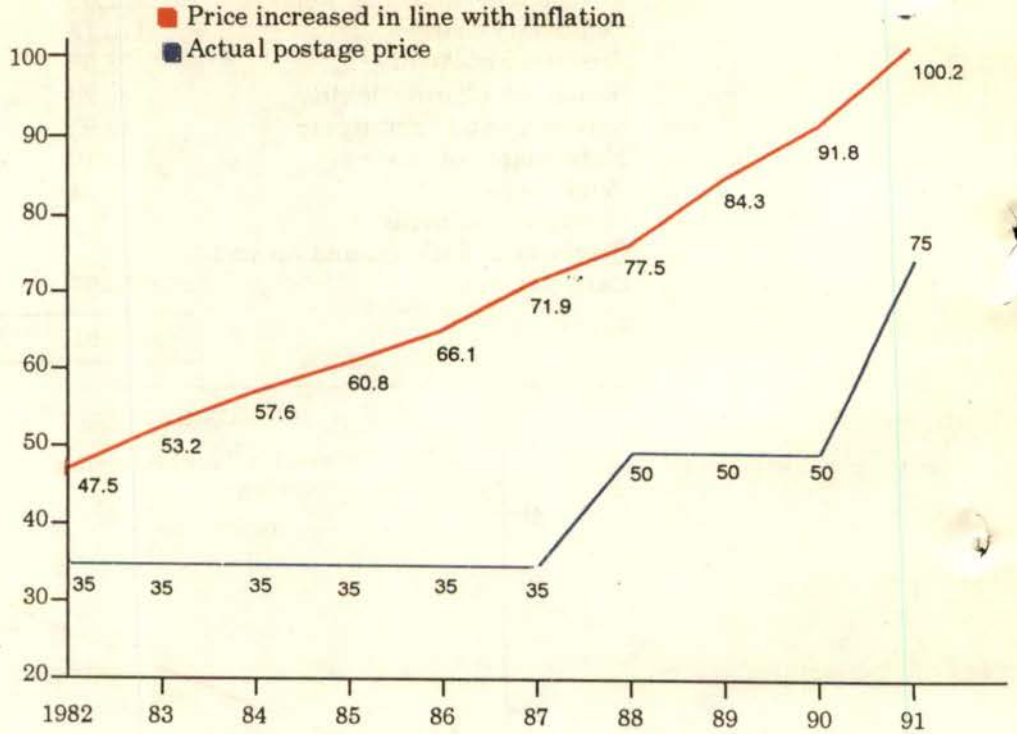

Revenue and Expenditure

(Millions of Rupees)

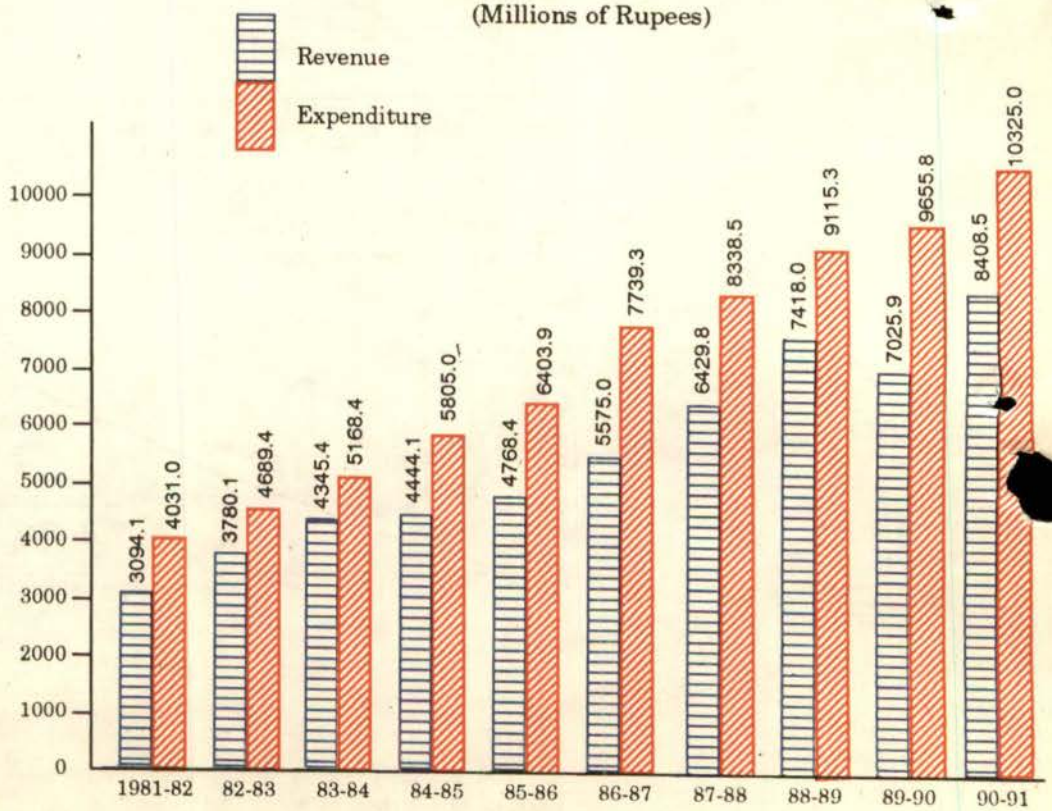

Cost of Service

The Cost & Revenue of main services for the year 1990-91 along with the position for the previous year is shown against each service below:

(Figures in Rupees)

Service	1989-90 Cost	1989-90 Revenue	1990-91 Cost	1990-91 Revenue
Postcard	1.11	0.15	1.17	0.15
Printed Postcard	1.07	0.40	1.09	0.60
Letter card	1.25	0.43	1.28	0.75
Letter	1.28	1.29	1.29	1.81
Parcel	17.10	10.25	14.61	14.31
Money Order	10.62	8.76	11.51	8.99
Registered	7.78	5.00	8.20	6.00
Insured	10.23	9.20	10.77	18.12
Packets				
Book Packet	1.63	1.20	1.58	2.42
Printed Books Packet	2.08	0.83	1.96	2.26
Others	2.29	0.99	2.15	2.11

Agency Services

In the year 1990-91, the Department's recovery of working expenses on account of agency services was:

(Rupees in crores)

Savings Bank & Savings Certificates	247.46
Postal Life Insurance	10.79
Payment of Railway Pension	0.66
Coal-miners'/EPF Pension	2.49
Customs Duty realisation	11.92
Military Pension	0.16
Others	2.28
Telegraph share	40.26
TOTAL	316.02

Capital Outlay

The gross outlay on fixed assets in the year was Rs 31.48 crores, of which 85.48% was on land and buildings and 14.52% on apparatus, plants and others. Capital Outlay on fixed assets rose to Rs. 424.82 crores at the end of the year. The net progressive capital outlay upto the end of the year financed from General Revenue was Rs. 346.36 crores.

HUMAN RESOURCES

Manpower

The personnel of the Department continued to be the largest resource in the Indian Postal System. The total staff strength as on 31.3.1991 was 5.92 lakhs. Of this, 2.99 lakhs are Extra Departmental Employees who largely provide rural services.

Postal Staff College

The Postal Staff College provides induction training to the directly recruited officers of the Indian Postal Service and Indian P&T Finance and Accounts Service and also organises refresher courses, seminars, workshops, executive and management development programmes. In all, 107 officers of different cadres including 8 officers from SAARC countries attended the training programmes conducted by the Postal Staff College.

The College was shifted to its newly constructed building at Ghaziabad with effect from 16.4.90 and the administrative and academic blocks started functioning with effect from 16.4.90 itself. The hostel block has also been completed in October 1990 and since then, all the in-service and induction trainees are living in the hostel block of the Postal Staff College.

Training Programmes

The Postal Staff College, Ghaziabad has organised following courses/sessions besides the usual Induction Training Programmes for IPS and P&T Accounts and Finance Probationers during the year 1990-91.

(i) Management Training Programme for Postal Executives from 22.10.90 to 1.11.90.
(ii) SAARC Course on Popularisation of EMS from 4-10 December, 1990.
(iii) Executive Development Programme held from 18-28 February, 1991.

Regional Training Centres

There are five Regional Training Centres for providing induction and in-service training to the operative as well as the supervisory staff including Postal Service Group 'B' Officers. These are at Darbhanga, Madurai, Mysore, Saharanpur and Vadodara. In all, about 14800 officials were imparted training during the year, 1990-91.

Syllabi for almost all the courses were revised in 1990-91, putting more emphasis on the latest rulings/instructions of the department, mechanisation, behavioural aspects of the officials while dealing with the public etc.

Recognition of Higher Performance

The Department gave "Meghdoot Awards" to the following employees for their outstanding and meritorious services:

1. Shri Bhavan Kumar, ED Telegraph Messenger, Punjab
2. Shri J.M. Rana, EDDA, Gujarat
3. Shri Chandeshwar Paswan, Postman, Bihar
4. Shri Relu Ram, Mail Overseer, Himachal Pradesh
5. Shri Sohan Singh, M.V. Mechanic, Delhi
6. Shri K.S. Thapa, Jeep Driver, Himachal Pradesh
7. Shri Champa Ram, Departmental Mail Runner, Himachal Pradesh
8. Shri Bant Singh, LSG, S.P.M. Punjab
9. Shri R.S. Kashyap, APM, LSG, Himachal Pradesh
10. Shri C.D. Mohanty, LSG, Asstt. RMS, Orissa
11. Shri S.C. Patyal, SDI (Posts), Himachal Pradesh
12. Smt. Vijayalakshmi K. Nair, LSG Supervisor, Maharashtra

Staff Welfare

The Postal Services Staff Welfare Board has been functioning under the Chairmanship of Minister of Communications. The objectives of the Board are to promote, develop, organise and exercise overall control in respect of staff amenities and welfare, sports and cultural activities in the Department. The financial resource of the Board is in the form of grants-in-aid from the Government. Voluntary contributions from staff and collection through sports and cultural activities, are organised by the subordinate formations.

The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, community centres, recreation clubs, financial assistance in the case of illness, death and natural calamities, educational scholarship, subsidy for excursion trips and grants to help handicapped staff and children, vocational training centres, creches, etc. During the year 1990-91, a sum of Rs. 90 lakh was spent on welfare activities.

Holiday Homes

During the year under review three new Holiday Homes were opened at Jammu, Puri and Kanyakumari. The Department is already running Holidays Homes in the following places for the benefit of its employees and their families:- Tirupati (Andhra Pradesh), Guwahati and Kaziranga (Assam), Rajgir, Deograh (Bihar), Dwarka (Gujarat), Srinagar (J&K), Trivandrum (Kerala), Matheren (Maharashtra), Shillong (Meghalaya), Gopalpur (Orissa), Udaipur (Rajasthan), Agartala (Tripura), Mussoorie (U.P.), Digha and Diamond Harbour (West Bengal).

Sports

All India Postal Services Tournaments in Volley Ball, Table Tennis, Weightlifting, Powerlifting, Body Building, Aquatic, Athletics and Cycling were conducted during the year. Sports persons from the Department participated in the National Championships in various events.

National Award

Shri K.K. Fazal Mohammed, Office Assistant in the Office of SSPO Ernakulam, Kerala, a handicapped employee received the National Award for 1991 as the best handicapped employee.

SC/ST Employees

The Department successfully implemented the Government instructions for reducing the backlog of various posts for SC/ST employees.

Use of Hindi in the Official work

The Department made concerted efforts to ensure the maximum use of Hindi as official language in its Headquarters as well as in its subordinate offices. The Hindi Salahakar Samiti of the Department provides supervision and guidance in matters relating to the compliance of official language policy. Official Language Implementation Committees have been constituted in the Divisions as well as in all the Circle headquarters and their subordinate offices.

Internal Work Study

Internal Work Study Unit completed and finalised the following studies:

- Norms for sanctioning posts of Public Relation Inspector (Postal).
- Franking Machines in Post Offices.
- Study and job evaluation of Charge hands and the grading of skilled artisans in MMS units.
- Review of forms.
- Norms for the staff connected with the sale of Kisan Vikas Patras in Post Offices.

ACTIVITIES
(April-December 1991)

Expansion of Network

The emphasis was both on expansion and improvement of postal operations. Expansion of the postal network in the rural sector continued. Efforts were also intensified to tone up efficiency of the rural post offices by intensive monitoring. The total number of post offices sanctioned during this period was 446. During this period, the new norms evolved by the National Institute of Rural Development, Hyderabad and accepted by the Government were applied for opening the post offices.

Speed Post

Speed Post was further strengthened through suitable publicity and marketing techniques. The extension counter at Faridabad was converted into a full-fledged Speed Post Centre with effect from 1st November, 1991. During this period, 144 pairs of stations were opened under point-to-point Speed Post service in the country. International Speed Post links were established with Malawi, Cyprus, Canada, Ethiopia, New Zealand and Sudan with effect from 1st April, 1991.

Modernisation

In the sphere of modernisation of postal operations, further progress mark was towards development of software for on-line SB operations. This was developed by the National Informatics Centre and the first sub-post office to utilise this was Indraprastha Head Post Office, New Delhi, on 1st April, 1991. Later similar computers for SB operations have been provided in six other Head Post Offices of Delhi Circle. Further, the ground work in connection with the procurement of automatic mechanical sorting plant for Bombay was completed during the period, which eventually culminated in signing of the agreement on 1st January, 1992 for the same.

Mail Box Scheme

Department has been facing difficulties in delivery of mail in multi-storeyed buildings as they are increasing in number not only in big cities but also in other towns. In order to help the postal staff as well as to avoid delays in deliveries, a statutory order was issued on 29th May, 1991 that those residing on the other floors, i.e. other than the ground floor, should provide mail box on the ground floor.

Insurance Limit

Limit of insurance was raised from Rs. 10,000 to Rs. 20,000 effective from 14th September, 1991.

Relations with UPU

India continued to play a leading role in the International postal affairs as a member of the Consultative Committee for Postal Studies of the UPU as also a member of the Asian Pacific Postal Union (APPU). In both these Unions, India holds important positions, namely, as Chairman of Committee 7 of the CCPS and the Chairman of Standing Committee on Technical Co-operation and Assistance of APPU. One-member delegation from India participated in the SAARC Study tour organised by Pakistan in April, 1991. Officers of the Department were also deputed to attend the SAARC Seminar at Sri Lanka in June, 1991 and the Technical Committee of Postal Services at Kathmandu in June, 1991. India organised a Senior Postal Management course for UPU member countries from 18th November, 1991 to 14th Decem-

ber, 1991. The course was attended by participants from 13 countries. An officer attended the Postal Management course at Asian Pacific Postal Training Centre, Bangkok from 3rd June, 1991 to 15th June, 1991. Officers were also deputed for the training courses under the Consultancy Mission sponsored by the UPU to the U.S.A. and Germany during this period.

Philately

During this period, India took part in several international Philatelic Exhibitions – in Bangkok from 4th to 13th August, 1991, in Peru from 8th to 29th August, 1991 and in Bonn from 21st to 25th October, 1991. Two circle level exhibitions were also held by Andhra Pradesh and Bihar Circles during this period. In all 46 commemorative/special stamps were issued.

Premises

Building activity continued to receive considerable attention. During this period, construction of 33 office buildings and 65 staff quarters commenced and 24 office buildings and 93 staff quarters which were on-going works at the beginning of the year were completed.

Special Recruitment Drive

In order to fill up the backlog vacancies meant for SC/ST, a special recruitment drive was launched in 1991. Under this drive, action was taken to fill up 2136 vacancies in different categories. Of this, 1562 vacancies have already been filled up.

Postmaster General's Meet

The meeting of the Heads of Circles was held on the 20th and 21st December, 1991. This Conference discussed number of major issues and took decisions on various subjects based on the recommendations of the sub-committees constituted for this purpose.

Official Language

During the period under report, the Hindi Week was observed in the Department as well as in the subordinate offices from 16th to 20th September, 1991. During the week, various programmes were organised and prizes given to the winners of the various competitions held in order to promote the use of Hindi in official work. The Department has already introduced incentive schemes like Dak Vibhag Rajbhasha Shield. Many officials were also awarded cash prizes and certificates of merit for their contribution in the progressive use in Hindi.

TABLE 1

(Rupees in crores)

Financial Working	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1. Receipts	557.50	642.98	741.80	702.59	840.85	960.00
Expenditure						
2. General Administration	60.28	68.67	72.91	80.25	83.28	105.47
3. Operation	664.22	754.22	775.64	864.29	905.49	1063.87
4. Agency Services	27.60	32.81	38.47	44.07	46.31	60.25
5. Audit and Accounts	19.56	23.10	25.76	28.99	30.88	41.86
6. Engineering Maintenance	12.18	13.03	14.50	16.24	11.48	27.48
7. Amenities to staff	8.56	7.93	11.30	11.51	10.67	17.14
8. Pensionary Charges	61.95	96.34	99.89	110.18	150.31	135.16
9. Stamps, Stationery & Printing	44.39	30.36	46.61	62.07	63.16	66.33
10. Depreciation	3.81	4.36	4.87	5.19	5.40	6.00
11. International Cooperation	0.55	0.66	0.66	0.76	1.09	1.32
12. Social security and welfare Programmes	0.09	0.12	0.12	0.25	0.19	0.22
13. Gross Working Expenses (Total of Items 2 to 12)	903.19	1031.60	1090.73	1223.80	1308.26	1525.10
14. Less-Credits to Working Expenses	129.26	197.75	179.20	258.22	275.76	310.00
15. Net Working Expenses (Item 13 minus 14)	773.93	833.85	911.53	965.58	1032.50	1215.10
16. Net Receipts (Item 1 minus 15)	(-) 216.43	(-) 190.87	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 255.10
17. Dividend to General Revenues	-	-	-	-	-	-
18. Surplus (+)/Deficit (-) (Item 16 plus 17)	(-) 216.43	(-) 190.87	(-) 169.73	(-) 262.99	(-) 191.65	(-) 255.10

TABLE 2

Capital outlay during and upto the end of 1990-91

(Rupees in Crores)

	During 1990-91	Upto the end of 1990-91
A.FIXED ASSETS		
1. Land	2.08	41.31
2. Buildings	24.83	350.68
3. Railways Mail Vans owned by Post Offices	-	8.61
4. Apparatus and Plant	0.52	14.08
5. Motor Vehicles	4.05	9.60
6. Other Expenditure	-	0.54
7. Gross Fixed Assets	31.48	424.82
8. Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Accounts	0.01	0.61
9. Deduct-Expenditure met from Posts and Telegraphs Capital Reserve Fund	-	1.29
10. Deduct-Amount of Contribution from Revenue	-	27.86
11. Deduct-Depreciation on historical cost transferred from Revenue	5.40	46.02
12. Total Deductions (i.e. total of Item 8 to 11)	5.41	75.78
13. Net Fixed Assets (i.e item 7 minus 12)	26.07	349.04
B. OTHER ASSETS		
14. Consumer Co-operative Societies Share Capital Contribution	-	-
15. Civil Engineering Suspense	0.07	(-) 2.68
16. Total Other Assets (Items 14 plus 15)	0.07	(-) 2.68
17. Total Capital Outlay Financed from General Revenues (Items 13 plus 16)	26.14	346.36
18. Deduct-Portion of Capital Outlay Financed from Ordinary Revenues	-	1.05
19. Total Capital Outlay (Voted) (i.e. Item 17 minus 18)	26.14	345.31

TABLE 3
Number of Post Offices as on 31st March, 1991

	States/Union Territories	Urban	Rural	Total	Area served by a post office (sq. kms)
1.	Andhra Pradesh	1404	14848	16252	16.92
2.	Assam	280	3483	3763	20.84
3.	Arunachal Pradesh	9	245	254	329.69
4.	Bihar	582	10694	11276	15.42
5.	Goa	56	182	238	14.46
6.	Gujarat	819	7873	8692	22.55
7.	Haryana	308	2214	2522	17.53
8.	Himachal Pradesh	101	2475	2576	21.61
9.	Jammu & Kashmir	195	1359	1554	143.01
10.	Karnataka	1323	8342	9665	19.84
11.	Kerala	686	4205	4891	7.94
12.	Madhya Pradesh	1071	9802	10873	40.78
13.	Maharashtra	1443	10463	11906	25.84
14.	Manipur	35	570	605	36.90
15.	Meghalaya	30	426	456	49.16
16.	Mizoram	39	299	338	62.37
17.	Nagaland	19	249	268	61.86
18.	Orissa	590	7210	7800	19.96
19.	Punjab	458	3321	3779	13.32
20.	Rajasthan	822	9048	9870	34.67
21.	Sikkim	13	142	155	45.78
22.	Tamil Nadu	2035	9942	11977	10.85
23.	Tripura	47	619	666	15.74
24.	Uttar Pradesh	2088	17051	19139	15.38
25.	West Bengal	1096	7264	8360	10.61
	Union Territories				
1.	Andaman & Nicobar Islands	12	85	97	85.04
2.	Chandigarh	43	6	49	2.32
3.	Delhi	423	115	538	2.75
4.	Dadra & Nagar Haveli	1	32	33	14.87
5.	Daman & Diu	4	14	18	6.22
6.	Lakshadweep	-	10	10	3.20
7.	Pondicherry	41	58	99	4.97
Total		16073	132646	148719	22.10

TABLE 4
SAVINGS BANK - Outstanding Balances

(Number in Lakhs)
(Amount in crores of Rupees)

	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount
Savings Bank	422	3012	439	3403	450	3564	476	3766	647	3976
C T D	55	570	52	560	57	499	67	383	83	270
Recurring Deposits	286	1263	236	1545	283	1850	334	2255	385	2638
Time Deposits	12	6457	10	5745	10	4987	10	3830	12	2973
National Savings Scheme	–	–	1	95	6	810	34	2516	30	4592
Monthly Income Scheme	–	–	1	228	3	792	13	1535	13	2340
Total	775	11302	739	11576	809	12502	934	14285	1170	16789
Savings Certificates		13431		16790		21340		27515		33320
Grand Total		24733		28366		33842		41800		50109

TABLE 5
Postal Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund
	No. of Policy (in Lakhs)	Sum assured (Rs. in crores)	No. of policy (in Lakhs)	Sum assured (Rs. in Crores)	(Rs. in Crores)
1981-82	1.13	106.9	9.30	590.4	157.3
1982-83	1.05	108.4	10.07	685.3	190.6
83-84	1.17	143.0	10.84	809.4	223.9
84-85	1.12	153.0	11.56	942.8	260.6
1985-86	1.01	160.4	12.16	1070.9	307.2
1986-87	1.03	179.3	12.81	1227.6	368.9
1987-88	1.20	232.9	13.62	1439.3	446.1
1988-89	1.37	294.9	14.58	1711.5	534.5
1989-90	1.63	432.5	15.79	2119.4	642.8
1990-91	1.56	476.3	16.92	2567.9	776.0

TABLE 6

Personnel :- Actual strength (including those on deputation and training outside the department) as on 31.3.1991.

A. Gazetted

Secretary (Posts)	1
Member, Postal Services Board	3
Secretary, Postal Services Board	1
Indian Postal Service	
Senior Deputy Director General/Chief Postmaster General	7
Senior Administrative Grade	75
Junior Administrative Grade	117
Time Scale	204
Postal Service Group 'B'	975
P&T Accounts & Finance Service	
Senior Administrative Grade	1
Junior Administrative Grade	11
Time Scale	26
Accounts Officers & Asstt. Accounts Officers	688
Central Secretariat Service	66
Civil Wing	
Chief Engineer	1
Others	238
Other General Central Services	192
Total	2606

Non Gazetted	Group 'C'	Group 'D'	Total
Directorate	455	161	616
Post Offices	198817	33938	232755
Railway Mail Service	27679	19729	47408
Mail Motor Service	2177	652	2829
Others	3915	3096	7011
Total	233043	57576	290619
Total Departmental			293225
B. Extra Departmental			298743
Grand Total (A+B)			591968

TABLE 7
NUMBER OF EMPLOYEES - SCHEDULED CASTES/TRIBES AS ON 31.3.1991

	Scheduled Castes	Percentage to Total No. of Employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total No. of Employees
Group 'A'	78	11.48	32	4.71
Group 'B'	213	11.05	39	2.02
Group 'C'	41559	17.83	13151	5.64
Group 'D' (Excluding sweepers)	10725	18.95	3533	6.24
Group 'D' (Sweepers)	1019	83.39	212	17.35

TABLE 8

NUMBER OF EMPLOYEES-EX-SERVICEMEN AS ON 31.3.1991

	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen
Group 'A'	1	–
Group 'B'	2	–
Group 'C'	2113	65
Group 'D'	576	37

Kidwaipuri Post Office Building, Patna

Tracking and Tracing Equipment - International Speed Post

Speed Post Business Centre - New Delhi